

*DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF RAILWAYS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): We shall now resume discussion on the working of the Ministry of Railways; Shri Neeraj Shekhar.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात शुरू करने से पहले ही आपसे यह आग्रह कर लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूँगा।

चूँकि मुझे भारतीय रेल पर बोलने का अवसर मिला, इसलिए मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब से मुझे भारतीय रेल में चलने का मौका मिला है, पिता जी के साथ भी और जब से राजनीति में आया हूँ, मैं बलिया भारतीय रेल से ही जाता हूँ। पिछले कुछ सालों में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, जो परिवर्तन आया है, वह स्वच्छता है। आज स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता है। मैं लगातार कई सालों से रेल से सफर करता आया हूँ। ट्रेनों में जो विदेशी पर्यटक चलते थे, जब वे जाने कि मैं एक सांसद हूँ, उन्होंने कई बार मुझे complaint की कि टॉयलेट साफ नहीं है, रिजर्वेशन होने के बाद भी मुझे ठीक से बैठने को नहीं मिलता है। अब यह जो परिवर्तन आया है, इसके लिए मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज स्टेशनों पर जो स्वच्छता है, उसको आप सब लोग देखते होंगे और पाते होंगे कि अब उसमें बदलाव आया है। अब स्टेशन्स साफ रहने लगे हैं, रेलवे लाइन्स साफ रहने लगी हैं। पहले रेलवे लाइन की तरफ कोई देख नहीं पाता था।...(व्यवधान)... आज रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में जो स्वच्छता है, उसको मैं सबसे बड़ा परिवर्तन मानता हूँ। जो ट्रेन में चलते हैं, उनके लिए आज यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। माननीय सांसद जी रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की बात बोल रहे हैं। इस संबंध में गुजरात का उदाहरण है, मध्य प्रदेश में जो स्टेशन बना है, वह विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बना है। मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जहाँ कोरोना काल में हर चीज़ में कटौती हुई है, मैं वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन लोगों ने capital expenditure में कटौती नहीं की, बल्कि इसको लगातार बढ़ाने का काम किया है। मेरे ख्याल से 2014 से पहले capital expenditure 45,000 करोड़ रुपए होता था, जो आज बढ़ कर 2,45,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह दिखाता है कि हम लोग काम के प्रति कटिबद्ध हैं और रेलवे के लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें साधारण लोग यात्रा करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो मैं मानता हूँ और जो मैंने देखा है, मैं जब से सदन में आया हूँ, तब से मैं लगातार बार-बार इस बात को उठाता आया हूँ कि पहले दो जनरल बोगीज़ होती थीं और उनमें सफर करना बहुत मुश्किल होता था। लोग जिस स्थिति में उसमें सफर करते थे, वह बहुत भयावह स्थिति होती थी, उसमें लोग एक के ऊपर चढ़े होते थे। मैं इसके लिए भी रेल मंत्री महोदय का

* Further discussion continued from 16th March, 2022.

आभारी हूँ कि अब दो की जगह चार जनरल बोगीज़ जुड़ने लगी हैं। मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूँ। मैं यह बात बार-बार उठाता था। मैं कई सालों से यह बात उठा रहा हूँ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो 'प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना' शुरू हुई है, जिसके लिए कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे, अगले तीन सालों में कम से कम एक सौ टर्मिनल्स बनेंगे, जहाँ पर कार्गो के लिए काम किया जा सकेगा। अगले तीन सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन्स चलेंगी, यह दिखा रहा है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो हाई स्पीड ट्रेन्स चलने वाली हैं, उनके लिए जो route तय किए गए हैं, मैं उस संबंध में बताना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि दिल्ली से कोलकाता का जो route है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग इस route के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस route पर भी हाई स्पीड ट्रेन जरूर होनी चाहिए।

मैं इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के बारे में जरूर कहूँगा, क्योंकि बलिया, जहाँ से मैं आता हूँ और गाजीपुर के संबंध में मैं कई साल से यह बात उठा रहा था। मुझे याद है कि जब 2010 या 2011 में मैं लोक सभा में था, तब कहा गया था कि इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और डबलिंग भी होगी, जो कि बनारस से छपरा का रूट है। पिछले दो-तीन सालों में यह जो काम हुआ है, इसमें वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हुआ है और डबलिंग का काम भी इस साल के अंत तक कम्प्लीट हो जाएगा। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी और रेलवे विभाग का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं हमारे माननीय मुख्य सचेतक जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया। मैं बलिया के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बलिया और गाजीपुर के बारे में जो कहना चाहता था, उस पर आना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। वहाँ पर कई छोटे-छोटे स्टेशंस हैं, जैसे ताजपुर है, रेवती है, चितबड़ागाँव है - यह कैसे हो रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्हें हॉल्ट स्टेशन घोषित किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों ने, विशेषकर ताजपुर के लोगों ने इसे सम्मान की बात से जोड़ लिया है कि पहले हमारा स्टेशन पूरा था, अब उसे हॉल्ट स्टेशन बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे अपने अभिमान से जोड़ लिया है - माननीय मंत्री जी से गुजारिश करिए कि उसे हॉल्ट स्टेशन न किया जाए। जहाँ तक मुझे पता है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताजपुर, रेवती और चितबड़ागाँव स्टेशंस का नाम काफी पहले से है, इसलिए उन लोगों को इससे एक कष्ट हो रहा है कि अब इन्हें हॉल्ट स्टेशन बनाया जा रहा है। मैं इस संबंध में मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि मंत्री जी इसे देखें और उन्हें पूरा स्टेशन रहने दिया जाए।

महोदय, हमारे कई पूर्व सांसदों ने मुझ से एक बात कही, उसे लेकर मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा। एक दिन सभी को पूर्व होना है। यह एक सत्यता है कि सब लोग एक दिन ex MP हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी, उन लोगों को आज जो सबसे बड़ा कष्ट है, वह reservation का है। उन लोगों को खुद आना पड़ता है। उन लोगों को पहले एक पासवर्ड भी दिया गया था कि उसका उपयोग हो सके, लेकिन उन्हें खुद आना पड़ता है, चिट्ठी भी लिखवानी पड़ती है और वह चिट्ठी डीआरएम को देनी पड़ती है। मैं आग्रह करूँगा कि जो हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद हैं, कम से कम उन्हें यह सुविधा दी जाए कि अगर वे अपने लिए reservation माँगते हैं, तो उनका reservation हो जाए और उन्हें इसमें सुविधा हो।

महोदय, बलिया रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने के लिए और कई छोटे-छोटे रेलवे स्टेशनों के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। वे पैसे कोरोना से पहले दिए गए थे, लेकिन अब काम थोड़ा धीरे हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि बलिया 1942 में आज़ाद हुआ था। हम इस बार आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, मगर 1942 में 15 दिन के लिए तीन जिले स्वतंत्र हुए थे, जिनमें एक बलिया भी माना जाता है, इसीलिए बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है, अतः आप बलिया का विशेष ध्यान रखें। वहाँ के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए कहा गया था, मैं इसके लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा।...(समय की घंटी)...

महोदय, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। जब भी मुझे रेलवे पर बोलने का मौका मिलता है, मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से बार-बार यह अनुरोध करता हूँ, जो 1975 के महानायक स्वर्गीय जयप्रकाश जी के बारे में है। वहाँ एक बकुल्हा स्टेशन है। उनकी जन्मस्थली भी वहाँ बगल में ही है। मैं बार-बार यह बात दोहराता हूँ, क्योंकि यह मेरी, बलिया के सभी लोगों की और पूरे देश के लोगों की इच्छा है कि उस बकुल्हा स्टेशन का नाम जयप्रकाश जी के नाम पर हो जाए। माननीय मंत्री जी, वह कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा स्टेशन है, लेकिन उससे सबका एक लगाव है। मैं यह बात दोहराना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल जी वहाँ गए थे, तब उन्होंने भी यह घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि इस पूरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इस रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा और हम लोग इसे जेपी के नाम पर करने का काम भी करेंगे। उस पूरे क्षेत्र को Sitab Diara कहा जाता है। महोदय, मैं यही सब बातें कहना चाहता था और फिर से यही अनुरोध करता हूँ। बलिया, गाजीपुर, इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान रहा है। जब गाँधी जी ने 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू किया था, उस समय इन सब क्षेत्रों ने बड़ा काम किया था। अब हमें 75 साल हो रहे हैं, इसलिए इन पर आपका विशेष ध्यान रहे, मैं आपसे यही अनुरोध और आग्रह करना चाहता हूँ। इसके साथ ही, मैं सभापति जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया, जय हिन्द!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you. Next speaker, Shri Derek O'Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, our second Railway Minister, Shri N. Gopalaswami Ayyangar from Tamil Nadu had a big idea, a great idea, which has been sustained now for 60-70 years. He came up with the idea of Railway Zones. It was not there before. After that, another big idea, which has sustained over five, six decades was the idea of Madhu Dandavate ji. His idea was that instead of the sleepers just being of wood, we should put cushions there to make a difference to the common people who travel by trains. It was a great idea which has sustained the test of time. Nitish Kumar ji came up with Tatkal scheme. Lalu Prasad Yadav ji came up with the Garib Rath scheme. It was his big idea. Mamata Banerjee came up with Vision-2020 Document, and, I will come to it later. Duronto Express was there. The Izzat Pass was there for those below the poverty line.

I want to ask this Government as to what is their one big idea from 2014 to 2021, which will sustain the test of time ten or twenty years from now. Oh!, why one, they will tell me that they have got five, six, seven ideas. Let us take them one by one. First is, Vande Bharat Express. In the Vande Bharat Express, the cost of a ticket is between Rs. 1,500 and Rs. 3,000. It is somewhere in this range. This is your big idea and you are entitled to it, keep it because your outlook is different from the outlook of Trinamool Congress and many other parties have as far as railways is concerned. For us, the Railways constitute the infrastructure for the fundamental right of every Indian citizen to move from point A to point B. It is the fundamental right as far as transport is concerned. You may look at it differently. We don't. So, this is for your Vande Bharat.

Let us come to your second so-called big idea. In 2017, you subsumed the Railway Budget into the General Budget. We objected to it at that time, and, we object to it today also. Former Railway Minister who is now the Chief Minister of West Bengal said, "This will damage the very core of the transport system". What is the benefit of this 'subsuming' that has taken place? Please tell us. About LIC, you said that 1.5 lakh crore. These are my direct questions, and, please address these questions in your reply. Why was only 30,000 crore of rupees given? What happened after the first tranche? Why is there no further funding? Tell us about the methodology of funding, tell us about the LIC interest rates, tell us about the repayment issues. Please address these issues in your reply and we will be happy to hear the same.

Let me now come to your third big idea, and, as I said, your big idea will never be in tune with our idea because your outlook towards the Railways is different from our outlook towards Railways, which is fundamental right of movement. Your third idea is, Train from Mumbai to Ahmedabad, call it super-fast or call it bullet train. There is nothing wrong with the bullet train maybe at some later stage. To make a bullet train costs Rs. 200 crores per kilometre. Our priority would have been a dedicated freight corridor for *sabji*, for *chawal*, for gram and for everything else at a cost of Rs. 25 crore per kilometre. I understand, and, I say this on the floor of the House that this bullet train is your vanity project. But since we are talking about big ideas, let us talk about some of those ideas which were promised to be done by 2022 and we are all so eagerly looking forward to it. Some of them are - farmers' income will double - by 2022; bullet train will come - by 2022; five trillion dollar economy - by 2022; water and toilet in every home - by 2022; electricity for all - by 2022.

For those of you who want to bring these high-speed trains, there is nothing against the high-speed trains, I would say, please think of a small railway station

called Kitham. It is a small town in Uttar Pradesh. Every day 96 trains whiz pass Kitham on the New Delhi-Agra route. Rakesh, if he wants to take a train, he would have to take the Agra-Delhi passenger train, which does not run on Sundays and the average speed of those trains is 30 kilometre/hour. Your priority; our priority.

Your priority - our priority. Now, let us come to your next big idea. I want to ask you, since we think it is a fundamental right of travel, who told you to shut the railway network down four hours before covid lockdown. The Railways is a precious resource of our country. You misused that precious resource. 120 lakh passengers travel daily long distance in the railways. Just look at this number - 120 lakh. With covid restrictions, you could cut the number down to 60 lakh per day. Instead of shutting it down in 4 hours, you could keep it open for 5 days. You would not have had the migrant crisis. And those videos from Muzzafarpur railway station, I don't want to remind you of that, of the little child with the dead mother covered because day before yesterday was the second anniversary of banging *thalis*. So, these are your 'big ideas'.

Now about 'Private trains', you say this is my 'big idea'. Let's ask you some questions on the private trains. Tejas trains halted for 8 months. In 2021, we were told that dozens of companies filed tenders. Whenever the RTI activists -- RTI activism is part of our democracy -- write to Railway Board, no data is available there. What is the communication for these private trains? Sir, there was an Empowered Group of Secretaries which was set up by the Railway Ministry. How many meetings have they had? Share with the MPs what was discussed at those meetings.

Your next big idea, you say, is federalism. I can give you 12-13 projects in Bengal -- everyone will have such projects in their own States -- where the allocation for them is Rs. 1,000 crores for the year. Whenever there is a problem with the railway work, they say 'State Government, land acquisition'. There are so many other examples to give you but I thought the real good one is beyond Bengal. It is for the Southern Railways, and this is from the Pink Book, which used to come out on the day of the Railway Budget. I know this subject a little. It takes you weeks to calculate. So, after some calculations, Southern Railways got less than Rs. 400 crores for new lines in the last four years. And the Northern Railways, if we add it up, comes to about Rs. 30,000 crores. ...*(Interruptions)*... I am not getting into the numbers, but conceptually, we talk so much about federalism. Where is the federalism? I can go State by State. Sir, I urge this Ministry, since you have a full railway department. Of course, the joke here was this. Some people were saying that we first discussed the North-East Ministry. Then we discussed the Scheduled

Tribes Ministry. Third, I was asked, "Which Ministry are you speaking on"? I said now we are discussing the PMO. Sir, I urge this Ministry -- they have got the numbers -- to share the figures as to what allocation in a State was and what percentage that State has been given. ...*(Interruptions)*... Maybe you had some big ideas about the North-East which we missed! The Imphal railway station is still under construction. Sir, we need another big idea for the North-East, which can't afford expensive freights. Do consider a way to make the freight rates affordable in the North-East. What steps has the Government taken to tap the Trans Asian Network? There are many of the South Asian countries which are closer. Look at these as big ideas. Well, as I said, your view on the Railways and our view on the Railways is different. I have a copy of the Vision Document. You are following some of this. We are happy. I am reading from the Vision Document when Ms. Mamata Banerjee was the Railway Minister. Raising the speed of the passenger trains from 130 to 160 kilometers - good, on track. Don't forget the suburban trains, Railways should set up 50 world class stations, all from the Vision Document 2010 - good. You have a lot of experience, Railway Minister, first as a bureaucrat and then with Adler Infrastructure.

So these are all good experiences for you. You said in the Lok Sabha, 'Who does the railway tracks belong to?' You said, 'Railways'. Who does the stations belong to? Railways. Who owns the train coaches? Railways. Who owns the signalling system? Railways. Then why is there any talk of privatization? I ask you this, Sir. Who owns the airports? Mostly Government of India. Who owns the runways? Mostly Government of India. Who owns the air infrastructure? Mostly Government of India. Who sold Air India? We think, Sir, this Government must focus differently. We will listen here to their seven ideas which are their great ideas. You compare those seven ideas to what were previously done by the Railway Ministry and then you look at what touches the lives of the people? Who is our audience? Who is our consumer? If you think your consumer or your co-consumer is the passenger, who gets on a train in Ahmedabad and has to reach Mumbai, no. Very good. Do that. But don't forget who the Railways is for. I will conclude by saying, please do remember you are doing nobody a favour.

We have two-three minutes' time and we have one more speaker. He will take two minutes after this. So I finish before time. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you, Derek ji. Next speaker is, Shrimati Priyanka Chaturvedi. She is not present. Shri Ajay Pratap Singh.

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे रेल विभाग के क्रियाकलाप पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सदन में रेल के इतिहास के बारे में बताया गया है, रेल की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और रेल विभाग के कार्यकरण के संदर्भ में भी पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने तर्क हैं। मैं जब रेल विभाग के बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो इसके कार्यकरण को नापने का मेरा अपना अलग ही पैमाना है। मेरा पैमाना मेरा गृह प्रदेश है, मेरा पैमाना मेरा मध्य प्रदेश है। रेल विभाग ने मध्य प्रदेश को क्या दिया, मध्य प्रदेश में रेल के कौन-से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके आधार पर मैं जो देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ, तब अपनी राय बनाता हूँ। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और रेल मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस वर्ष मध्य प्रदेश के लिए रेल विभाग का आवंटन ऐतिहासिक है। इतिहास में कभी इतना पैसा मध्य प्रदेश राज्य को नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश, देश का हृदय प्रदेश है। वह भौगोलिक दृष्टि से देश के बीचों बीच स्थित है। इससे लोगों को यह लगता है कि मध्य प्रदेश में रेल का बहुत अच्छा संजाल/नेटवर्क होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के लगभग 20-22 जिला मुख्यालय अभी भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रेल लाइन का औसत किलोमीटर अभी भी देश के कई बड़े राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इस वर्ष माननीय रेल मंत्री जी ने मध्य प्रदेश में रेल के लिए लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का आवंटन दिया है।

12 हजार करोड़ रुपये के माध्यम से कई जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें गति आएगी और वे पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। मैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का उल्लेख करना चाहता हूँ। रतलाम, महु और अकोला प्रोजेक्ट को जो आवंटन दिया गया है, उसके माध्यम से इंदौर और मुम्बई के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम होगी, तो गति तेज होगी, समय की बचत होगी और आवागमन में सुविधा होगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है - इंदौर-दाहोद, जो वर्तमान में 375 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के पश्चात् यह दूरी घटकर 205 किलोमीटर रह जाएगी। इंदौर-उज्जैन की जो रेल लाइन है, उसके दोहरीकरण के लिए भी 1,353 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। झांसी और बीना दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेशन्स हैं और दक्षिण भारत को जाने वाली अधिकांश ट्रेनें इस मार्ग से गुजरती हैं, तो ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए यहां पर तीसरी रेल लाइन की आवश्यकता थी। इस मार्ग पर रेल लाइन का तिहरीकरण किया जा रहा है। ग्वालियर और श्योपुर - श्योपुर मध्य प्रदेश का एक अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है, इस बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय रेल मंत्री महोदय ने इसके लिए 2,912 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके माध्यम से श्योपुर न केवल रेल के मानचित्र में आएगा, अपितु वहां अनेक तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी और साथ ही रोजगार और व्यापार बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन है - धार से छोटा उदयपुर। इसके लिए प्रारंभिक रूप से सौ करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह रेल लाइन व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस रेल लाइन के माध्यम से इंदौर, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, उसकी पहुंच गुजरात के पोर्ट तक हो जाएगी। इसके माध्यम से इंदौर में व्यापार खूब फलेगा-फूलेगा और उसका लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगा।

अब मैं अपने गृह जिले की भी बात करना चाहता हूँ। ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का शिलान्यास 1997 में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। इस रेल लाइन के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस रेल लाइन में रीवा से सीधी के

बीच में जो खंड है, उसमें दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक चुनौती सोन नदी पर पुल के संबंध में थी, जिसमें काफी लागत आने वाली थी और अन्य तरह की तकनीकी बाधाएं भी थीं। वे सारी बाधाएं दूर होकर, अब वह पुल बनकर तैयार है। दूसरा, रीवा से सीधी के बीच में जौ कैमोर पहाड़ है, उसको पार करना भी एक चुनौती थी, लेकिन वह चुनौती भी पार कर ली गई है। वहां सुरंग का निर्माण हो चुका है। अब छुट-पुट जो आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति हो जाएगी और हम यह विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में यह रेल लाइन भी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेल लाइन का शिलान्यास 1997 में हुआ, लेकिन इसकी चर्चा आज़ादी के पहले से हो रही है। केवल चर्चा होती थी, लेकिन कभी उस रेल लाइन पर काम नहीं होता था। काम अटल जी के कार्यकाल में शुरू हुआ और आज वह काम हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इस सदन में अनेक लोगों ने मनुष्य की, विशेष रूप से भारत में एक आम आदमी की औसत आयु की चर्चा की है। भारत में 69 वर्ष औसत आयु है और मुझे लगता है कि सदन में हम जितने लोग बैठे हुए हैं, दो-चार अपवाद छोड़ दिए जाएं, तो अधिकांश लोग उस औसत आयु के पैमाने पर जीवन के उत्तरार्ध में हैं। मैं भी लगभग जीवन के उत्तरार्ध की ओर ही हूं।

यह जो ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन है, यह हमारे सीधी और सिंगरौली जिले के लोगों के दिल की धड़कन है। यह उनके दिल में बसती है। इसकी चर्चा करते हुए, इसको सुनते हुए अनेक पीढ़ियां गुजर गई हैं। वर्तमान पीढ़ी भी इस रेल लाइन के लिए बड़ी उत्सुकता से देख रही है। उनके साथ-साथ मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस रेल लाइन के संदर्भ में इतिहास का भाग न बनूं। ...**(समय की घंटी)**... मैं अपने जीवन काल में इस रेल लाइन को पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, न केवल इसे पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, अपितु इस रेल लाइन के पूर्ण होने के पश्चात् रेल में बैठकर सीधी तक जाना चाहता हूं। ...**(समय की घंटी)**... मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्य पूरा होगा और हमारे सीधी और सिंगरौली के लाखों नागरिकों के साथ मेरा भी यह सपना साकार होगा।

महोदय, मेरे अंचल की जो आकांक्षाएं हैं, उनको भी मैं मुखरित करना चाहता हूं, उन्हें माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। वर्तमान समय में कोविड के दौरान बहुत सारी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अजय प्रताप सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अजय प्रताप सिंह : सर, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। सर, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्ववत् जितनी ट्रेनें हमारे अंचल में चल रही थीं, जितनी भी ट्रेनें हमारे रीवा से चल रही थीं, सिंगरौली से चल रही थीं, शहडोल से चल रही थीं, अनूपपुर से चल रही थीं, उन सारी की सारी ट्रेनों को आप यथावत् प्रारम्भ कर दीजिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा रीवा कमिश्नरी हैडक्वार्टर है, यह बहुत पुराना शहर है। यह 16वीं शताब्दी से बघेल राजवंश की राजधानी रहा है, यह आज़ाद भारत में विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब उससे यह दर्जा छिन गया, इसलिए हमारा रीवा विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। इसका यह गौरव आप वापस लौटा

सकते हैं। अभी आपने रीवा को दिल्ली से जोड़ा हुआ है, अगर आप रीवा को देश के चारों महानगरों से जोड़ देते हैं, आप इसे मुम्बई से जोड़ दीजिए, चेन्नई से जोड़ दीजिए, कोलकाता से जोड़ दीजिए, तो रीवा तेज़ी से विकास करेगा और रीवा के माध्यम से पूरा बघेल खंड विकास करेगा। मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री जी मेरी इस बात का संज्ञान लेंगे।

महोदय, मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। शहडोल से रीवा रेल लाइन के बारे में मध्य प्रदेश की विधान सभा में एक संकल्प हमारे सीधी के विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया था और वह संकल्प सर्व-सम्मति से पारित हुआ था। वह संकल्प यहां पर भेजा भी गया है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वे उस संकल्प पर संज्ञान लें। वे उस रेल लाइन का सर्वे करवाएं और अगर वह रेल लाइन निर्मित होती है, तो हमारे अंचल का जो वनवासी क्षेत्र है, हमारे अंचल का जो गरीब आदमी है, हमारे अंचल का जो मजदूर व्यक्ति है, उसकी आकांक्षाओं को बल मिलेगा और उसके सपने पूरे होंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर, श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार ।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministry of Railways.

At the outset, I congratulate the hon. Minister of Railways, Shri Ashwini Vaishnaw for successfully testing *Kavach*, indigenous automatic train protection system. Indian Railways is the third largest railway network in the world. It has over 68,102 route kilometres under single management. It is also one of the major employment providers in the country. Lakhs of posts in the Railways including in safety-related departments like signalling, track maintenance are left vacant. I urge the Minister to take necessary steps to fill up these vacancies.

Now, I come to the railway projects pertaining to my State Andhra Pradesh. There are 33 projects -- 16 new line and 17 doubling -- costing Rs.63,731 crores covering a length of 5,706 kilometres falling fully or partly in the State of Andhra Pradesh and are under different stages of planning, approval and execution. In respect of my Unstarred Question 756 dated 3.12.2021, Shri Ashwini Vaishnaw has given a written reply in respect of six projects on cost sharing basis with the Andhra Pradesh State. For investment of the projects Nadikudi-Srikalahasti new line, the State Government has to deposit Rs.1,315 crores. For Bhadrachalam-Kovvur new line, the Andhra Pradesh Government did not give consent. About Vijaywada-Gudivada-Bhimavaram-Narsapur-Gudivada etc., 50 per cent of line is about for Rs.1,400 crores. Kadapa-Bangalore new line is also for Rs.189.94 crores.

Sir, Kotipalli-Narsapur, it is a long-pending demand, is Rs. 358 crores. Tumkur-Rayadurga new line, the Government has to give consent, and the Andhra Pradesh Government did not do it. The Government of Andhra Pradesh is not depositing their outstanding share in cost sharing projects. ...*(Interruptions)*... This is affecting the execution of these projects. This the reply given by the hon. Railway Minister.

Sir, due to unfortunate situation of State of Andhra Pradesh, the State Government has decided not to release its share of fund required for project implementation. The State of Andhra Pradesh is on the verge of disaster. The State is in mortgage. Government lands and properties even the capital of Amaravati lands are up for sale. ...*(Interruptions)*... Future revenues are being escrowed to raise borrowings to meet the present daily expenses. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: The State is in a vicious debt trap with the Government taking loans to repay debt and the future of the people of the State is gloomy as the state is being steered in a reverse direction. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): No running commentary, please. ...*(Interruptions)*... Please, no running commentaries. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: No developmental activities are undertaken by Government of Andhra Pradesh, including maintenance of existing infrastructure facilities. ...*(Interruptions)*... Mandatory constitutional provisions are also being violated by the Government of Andhra Pradesh, despite cautions given by the Central Government. Under these circumstances, I urge the hon. Minister to be magnanimous in the case of Andhra Pradesh and come with an alternative to complete these projects so that developmental activities in the State may not be hindered.

As per the provisions of the Andhra Pradesh Reorganization Act, under Section 93 read with 13th Schedule, Clause 8, Indian Railways shall, within six months from the appointed day, that is, 2nd June, 2014; examine establishing a new Railway zone in the successor State of Andhra Pradesh and take an expeditious decision there on. As per Clause 12 of 13th Schedule, the Government shall examine the feasibility of

metro Rail facility in Visakhapatnam and Vijayawada Guntur-Tenali Metropolitan Urban Development Authority within a period of one year from the appointed day, i.e., 2/6/2014 and take expeditious decision there on. Till now, both the projects have not been implemented. In the year 2019, the then hon. Railway Minister, Shri Piyush Goyal, came to Visakhapatnam and announced that the Central Government was going to set-up a new Railway Zone under the name of South Coast Railway Zone. In 2020-21 Budget, Rs. 170 crores have been allocated. In 2021-22 Budget, Rs. 40 lakhs only allocated. In 2022-23 Budget, no allocation has been made. The people of Andhra Pradesh are suspecting that the new South Coast Railway Zone can be operationalized or not, that too, the people of Andhra Pradesh are not going to accept the new Railway Zone without Waltair Division. For the purpose of new Railway Zone, cancellation of creating of existing Waltair Railway Division is unjustified and unreasonable. Every time, the hon. Railway Minister says that the Central Government is fully committed to operationalise the South Costal Railway Zone at the earliest. But, it has to be completed in a time-bound manner. Already 8 years are over. We are not demanding bullet trains, but only the existing Railway Zone. Sir, the Andhra Pradesh Capital Amaravati has to be connected with Railway facility.

Sir, Vijayawada Railway Station is one of the oldest railway stations. It is the 4th biggest busiest junction. But till today, the Vijayawada Railway Station is lacking proper amenities for the passengers and other infrastructure. I request the hon. Minister to take immediate steps to make Vijayawada Railway Station as a world class railway station in all respects.

Finally, Sir, I urge the hon. Minister to take up all projects in the State of Andhra Pradesh and complete the same without waiting for deposit of State contribution for the above projects in view of the pathetic alarming situation prevailing in the State of Andhra Pradesh due to financial anarchism of the present YSRCP Government. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया। आप गुजराती में बोलेंगे?

SHRI RAMBHAI HARJIBHAI MOKARIYA (Gujarat): * "Hon. Vice-Chairman Sir, thank you for giving me an opportunity to present my views on the discussion of the working of the Ministry of Railways. Once in a dilapidated condition and moving with a slow pace, the railway has picked up momentum since 2014 under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Not only that, the railways have undergone a radical

* English translation of the original speech delivered in Gujarati.

change. At present about 800 crore passengers travel through Indian Railways every year. Sir, at one point of time, travel by railways was considered as a mode of transport for extremely poor people but today due to punctuality, cleanliness and safety of the Indian Railways a big change has taken place. Behind this is the foresight and deep thinking of our hon. Prime Minister and hon. Railway Minister. They have thoughtfully removed the age-old obstacles and barriers that hindered the development of railways. Not only that, the railway stations of the past, which were full of dirt and garbage, have been replaced by clean, neat and modern railway stations. Earlier, there were no facilities for senior citizens, disabled and sick persons at railway stations but today at every railway station, all the necessary facilities like escalators, passenger lifts, toilet blocks, potable drinking water, retiring room, waiting room equipped with modern facilities, fast moving trains, over-bridges, new cover sets etc. are available. In this way, Indian Railways has succeeded in winning the trust of the people of the country. The reason behind this is only being Gujarati. Our Prime Minister is a Gujarati, our Railway Minister is also a Gujarati, our Smt. Darshanaben is also a Gujarati and I am also a Gujarati. A Gujarati person works with a great zeal wherever he goes. Sir, the number of railway stations and booking offices has been increased for the convenience of the people. Today, the annual revenue of the railways is Rs 2 lakh crore. About 1400 million tons of cargo is transported through railways every year. The main reason why Indian Railways is on the path of progress today is the Government led by hon. Prime Minister Narendra Modi. After 2014, the Railway Budget has been gradually increased. Sir, through you, I would like to inform this House that the railway budget in the period between the years 2009 and 2014 used to be around Rs. 45,800 crore per annum which has increased to Rs. 2,45,800 crore in the year 2022 - 2023. This is a five-fold increase. My friends of the Congress were saying that we should also count what they did. So I have to tell my friends in the Congress that they have done a lot too. There has also been the Bofors scandal and they have won only 2 seats out of 403 in Uttar Pradesh. Article 370 in Jammu and Kashmir has been repealed by us. All the tasks kept pending by you have been accomplished by us. That is why we are sitting here. If you wish to continue sitting in the opposition, please do some work. Then your 2 seats will not reduce to zero.

Sir, a budget of Rs. 4,745 crore has been allocated for Gujarat. On behalf of the people of Gujarat, I congratulate the hon. Prime Minister. I thank the hon. Prime Minister for bringing about a lot of changes in the railway lines of Gujarat. Many important railway projects have been completed in Gujarat. With this, new railway lines have been added, many schemes related to gauge conversion and electrification

have been completed. Sir, today, the Indian Railways has become self reliant and is moving forward. Railway accidents have become a matter of past. Earlier, many railway accidents took place and the Railway Minister as well as officials had to rush to the spot of accident and declare compensation. But accidents have become negligible over the years. For that, I thank the Railway Minister Shri Ashwini Vaishnavi. During the tenure of this Government and under the leadership of Prime Minister, Shri Narendrabhai Modi, along with modernization of railways, re-naming of railway stations is also taking place. The railway station with the name Habibganj is now known as Rani Kamalapati. It is a great pleasure. I am also very proud of Gandhinagar in Gujarat. Hon. Vice Chairman Sir, I come from Saurashtra and therefore cannot resist the temptation to put forward my demands regarding railways. I urge you to add Rajkot Railway Station to the list of world class railway stations. I also urge you to modernize the goods sheds. My demand is to start Ro-Ro service in Rajkot division. More arrangements need to be made for the fertilizer racks. The people of Saurashtra are very religious. Haridwar is a major center of faith for Hindus. Hindus frequently visit Haridwar. At present the train from Rajkot to Haridwar runs once in a week. If this train starts running daily, then, more people can travel to Haridwar. Even during the difficult times of Covid-19, under Modiji's leadership, Indian Railways has done a commendable job not only for the movement of passengers but also for the delivery of medicines, oxygen and vaccines. I heartily congratulate you for this. I request the hon. Minister that the unfinished work of Broad Gauge in Gujarat should be completed immediately. Along with this, I demand that the existing meter gauge railway lines be converted to broad gauge lines. A Railway University will be set up in Vadodara as per the announcement made by the hon. Prime Minister, Shri Narendrabhai Modi. This is a matter of admiration and joy. A Railway University was very much necessary for a progressive state like Gujarat. This is a matter of pride. Speaking of new trains, Vande Bharat train was introduced in the year 2019. This train has been manufactured in the lines of Aatma Nirbhar Bharat and it uses cent percent indigenous technology. This train has made India famous internationally. The Vande Bharat train is in no way inferior to the trains manufactured in Europe, Japan and other countries. Trains manufactured by other countries have a manufacturing cost of Rs 190-200 crore whereas Vande Bharat train has been manufactured at the cost of Rs. 110-155 crore. Not only this, the state-of-the-art technology has also been used in this train. With this I would like to make a suggestion that wherever railways have surplus land, it should be used commercially. Also, my suggestion is to plant trees in such fallow land. Doing so will increase greenery."

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मोकरिया जी, प्लीज़ समाप्त कीजिए।

SHRI RAMBHAI HARJIBHAI MOKARIYA: Hon. Vic-Chairman Sir, this is my Maiden Speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Is it your Maiden Speech? Please conclude.

SHRI RAMBHAI HARJIBHAI MOKARIYA: "Sir, I would like to say that yesterday one of the Hon. members said that former Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, introduced the policy of liberalization in India. I also request for privatization and liberalization of the railways. Liberalization has taken place in the airline sector, post offices and the telecom sector. Liberalization breaks the monopoly and in this age of competition people and consumers need to be facilitated. Shri PV Narasimha Rao made a few efforts for the construction of Ram Mandir. But it is sad to say that he did not get the place that he should have got in Delhi. It is also a pity that his mortal remains had to be taken to his homeland for cremation. This is a very serious matter. You praise your Prime Minister but it is a pity that you could not allot even three yards of space for him in Delhi. Prime Minister Shri Narendrabhai Modi has built the Ram Mandir, repealed Article 370 and after doing all this, we have won more seats. You need to understand why you are losing seats. If you want to do a good job as an opposition party, you are requested to support the good work done by the Bharatiya Janata Party. Jai Hind, Jai Bharat."

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, we all know that the Railways is called as the lifeline of India and covers from Kashmir to Kanyakumari. It carries the people from rural to urban. An average Indian citizen is dependent on Railways as a preferred mode of transport. Definitely, Sir, it is the duty of Railways to give high-priority to safety and security of the passengers. Sir, I press upon the need that Tamil Nadu needs more projects, more attention from the Ministry of Railways. Sufficient allotment of funds is needed for the State of Tamil Nadu because not only the new projects, even a lot of old projects are also pending in the State. Sir, things like gauge conversion, electrification, doubling, over-bridge, subway, modernisation, stoppages, new railway routes and especially electrical operation for human-operated crossing, all these can be done phase-by-phase. Sir, I request the Minister that timely start of work and completion of that work within stipulated time is definitely the need of the hour. Sir, stoppage of train at important towns seems to be very

important. It may be a temple town, a business town or a tourist town. For example, in Thanjavur District, Kumbakonam town is a temple town near Papanasam Constituency. Sir, stoppage of two express trains there is very important and the Minister has also written a letter positively in this regard. I request the Minister for the same. This is a good ticket revenue-yielding Station from Tiruchirappalli of Southern Railway under NSG-5 category. Sir, concession is needed for disabled, senior citizens, sports person and other valid categories. I press the need for it. Sir, I want to give two important suggestions before I complete. One, I request the hon. Minister to kindly reconsider establishing non-air-conditioned first class coaches in all major trains for the benefit of passengers with respiratory illnesses like Ashtma, Bronchitis and other such diseases. Sir, during Covid-19 pandemic, we have seen that the Railways rose to the occasion by running special trains and also providing isolation coaches which was appreciated whole-heartedly by the people of India. Sir, another important suggestion is that IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, is today engaged in promoting tourist activities only. It is one of the designated ticketing agencies for Government employees availing Leave Travel Concession (LTC). Sir, IRCTC may leverage this status to tap the tourist potential of India, especially in Tamil Nadu by offering packages for centres like Mahabalipuram, Thanjavur, Madurai, Kanyakumari, Nilgiris, Kodaikanal and other places with historical and cultural centres. This is for the promotion of tourism. At present, Sir, the tickets purchased only from IRCTC counters are eligible for LTC claims. The eligibility may be extended to the tickets purchased online from IRCTC website also. This will save a lot of time of Government employees who otherwise have to stand in queues for buying tickets during their office working hours. I hope the hon. Minister will consider my requests favourably and act upon them positively. Thank you, Sir.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. * "Sir, I too know Gujarati but since I have not informed the Chair in advance, I shall speak in English."

Sir, I rise to speak on the Demands for Grants under the Ministry of Railways. Sir, under the able-leadership of our Prime Minister, there has been a record allocation of Rs.1,37,000 crores for the Railways. There are a lot of new initiatives being taken by the Ministry. The Railways has to develop new products and efficient logistics, services for small farmers, and for small and medium enterprises, integration of rail network to provide seamless solution for movement of parcels.

* English translation of the original speech delivered in Gujarati.

आजकल online shopping का जमाना है। So, the railways will play a very important role in these logistics. There is Pradhan Mantri Gati Shakti Cargo Terminals and multimodal logistic facilities to facilitate transportation of cargo and there will be 100 such terminals in the next three years. Regarding multimodal connectivity between mass urban transport and railways stations, Sir, under the Kavach Atamanirbhar Bharat, 2,000 kilometers railway network will be brought under Kavach for safety and augmentation in 2022-23. Sir, another very important step taken by the Railway is the introduction of Vande Bharat 400 new generation trains for better efficiency and passenger riding comforts. Sir, for the first time, these trains will be made of aluminum instead of steel. So, it will increase the efficiency and they will be made safer. Sir, 102 such trains are already in the pipeline. Sir, the Finance Minister has also proposed one-station-one-product to help local businesses and supply chain. There has been a huge push in railway electrification. Sir, there have been various investments physical targets set, construction of new lines, gauge conversion, doubling of lines, track renewals, electrification, rolling-stock of locomotive coaches and wagons. Sir, a very important point, especially for me, is the gauge conversion. I come from Dungarpur in Rajasthan and they just completed our gauge conversion between Ahmedabad and Udaipur and Dungarpur comes on the way. Sir, I have some issues which I have pointed out to the Railway Minister. One is the level crossing at Balwara Phatak No.151. It is the main road that goes from Dungarpur to Ahmedabad and thousands of people go to Ahmedabad to work from Dungarpur, but there is a level crossing there whereas underpass has been made in all along the villages that come on the way. So, I would request the Minister to make an ROB and he has very kindly agreed. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please address the Chair, Dungarpurji. ...*(Interruptions)*..

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR: So, the other point is about the Ratlam-Banswara-Dungarpur rail line. The State Government over the years-- we have had two Governments-- have not been able to contribute their share to the rail line. It is very important that now there is a change in policy and the Centre should take up the total construction of the rail line between Ratlam-Banswara and Dungarpur. The State can facilitate in land acquisition, but the Centre has to pay the compensation. This is a very important point, and I hope the Railway Minister will consider this and change the policy so that we can have a railway line. Otherwise, no Government will ever be able to afford the compensation. The other very important

point or issue to be taken up by the Railways is the 'Look and Act North East Policy', Sir. It is a very important proposal in these times. Sir, there has also been increase in rail connectivity to Nepal; there has been rail connectivity to Bangladesh. There are new lines and doubling.

3.00PM

That is a very important step. All gauge conversion work in the North-East region has been completed. This is a very important thing. In today's time, railways will play a very important role in the logistics and since a lot of these lines will go to our border areas, and to facilitate the movement of heavy equipments of the Army, Railways will play a very important part. The Minister should consider making special rakes, coaches and special railway equipments to transport tanks and other heavy equipments. So, one train can transport to the border areas hundreds of trucks which transport equipments. So, in future, looking at the world situation--today we don't know where we are going--I feel that the Railways will play a very, very important part in future in transporting the heavy equipments of our armed forces. We have two very dangerous neighbours. We have our borders from the deserts of Rajasthan to the highest mountain ranges in the world where our Army is posted. It is a very crucial part that the Railway will be playing.

Another important point is tourism. The passenger expects safety and the Railway is also introducing aesthetically designed vistadome coaches on the tourist routes. This is another important scheme. Steam engines and steam tourism should also come into play. For the private train operations, there have been some bids, but they are not very successful. The other issue is that the railway is also considering land monetisation and RLD has been involved in monetisation of identified railway assets of 111 railway parcels, 84 railway colonies and 4 railways in Darjeeling, Kalka, Nilgiri... *(Time-bell rings)* ... Sir, I am given ten minutes!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): No, eight minutes. Please conclude.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR: Sir, the National Railway Plan is also another important step. The Indian Railways is restoring its full capacity to pre-Covid level. Indian Railways plays a crucial role and is one of the seven engines of growth. ...*(Interruptions)*... It is among the Gati Shakti initiative. The other big thing is the new Bullet Trains that will be introduced in high speed railway corridors. There would be an upgradation of railway stations. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR: Sir, today, Indian Railways is the fourth largest rail network in the world and the second largest in Asia.

Finally, I would like to say:

*"गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है,
चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है
गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।"*

और सर, आप घंटी बजा रहे हैं।

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, with your permission, I would say a few words. I am very happy that everybody is praising; even Shri Brittas is also praising our Railway Minister, Ashwiniji, now everybody--I don't know for what reason--maybe, they are having their own reasons for Railways. I feel that the discrimination against the South is not just with Ashwiniji only. It is all over the world! North America, South America, everywhere, always north is at the top. In our case also! But, my problem is, in the south, as Dr. Kanimozhi and others said, they are discriminating against Kerala. So, we want to have a separate zone. Otherwise, Kerala will never escape from the south discrimination also! That is why, my request to our Ashwiniji is to somehow see to it that the Kerala Zone is created. Since how many years we are asking, but there will always be excuses!

Sir, I am not going to talk about the railway network all over the country. I would restrict my request to my region. These are small issues, which need just a signature from Mr. Ashwini to be looked into. We approached the Chairman, Railway Board, to request for a change in the train timings, from 7.00 a.m. to 5.30 in the morning, so that we could have connecting trains. We have made recommendations from our level and at the level of the Palakkad DRM, but it is not happening. Everything has to go through the Railway Board.

Sir, I am making just two-three simple points. There is a train running from Nilambur to Trivandrum known as Rajya Rani Express. That is a train that caters to patients undertaking cancer treatment. The train caters to the Cancer Institute in Trivandrum from the Malabar side. We don't have any cancer centres. That stops at Kochuveli. From Kochuveli, again, they have to travel seven kilometers into the town. They say that there is no space in Trivandrum. I would request that if there is no

space, then they can consider the train from Nagercoil to Trivandrum. It has been sanctioned recently. It is seven kilometers from Trivandrum to Kochuveli. At night and through early morning, these poor patients come all the way from our place to Trivandrum and, similarly, from the Cancer Center to Kochuveli. The train ticket may cost Rs. 150-200. We want AC trains. Somebody here was saying that no AC trains are required. There is only one AC sleeper coach. Let it be there. Don't stop it citing Covid. But from Kochuveli, for a distance of seven kilometers, autorickshaws charge Rs. 300 to Rs. 500 early in the morning from the Cancer patients. It is free in the railways, but at night they are charging the patients Rs. 300 to Rs. 500. They are being exploited. From Nagaercoil to Trivandrum, it is just seven kilometers. That may be provided for so that all these problems are over. They talked about LHB coaches and Vistadome coaches. Our place, Nilambur is famous for teak. Somebody was saying that the railways are being used to transport teak from India to the UK. Nilambur teak is famous all over the world. So, they constructed the railway station there. That is what was told. Now it is a big railway line. Please reinstate that train. After Covid, it was stopped.

Sir, I am not demanding too many things. I am just asking for two-three things -- resumption of the Maveli-Malabar-Parasuram Rajya Rani Express, the Mangala Lakshadweep Ernakulam-Ajmer Express and upgradation of old coaches with new coaches. You won't believe, Sir, our old rail coaches are infested with cockroaches. You can't imagine how we are travelling.

Sir, these are the few points that I wished to tell the Minister about. I would request him to look towards Kerala, at least, once. We hear a lot about Gujarat. Everything from Narendra Modi to God knows where.... *...(Interruptions)...* So, please look at our case also.

SHRIMATI ROOPA GANGULY (Nominated): Sir, thank you for allowing me to speak on the discussion on the working of the Ministry of Railways.

Railways are an integral part of the life of a common man. No other means of transportation captures the imagination of people like the Railways do. In Indian movies too, many iconic scenes had railways in the background. We still have. Who can forget the scenes from *Pathar Panchali* or *Nayak* by Shri Satyajit Ray and many other films by famous Directors? Toy trains in Darjeeling, Shimla and Ooty, let people witness the beauty of nature and Konkan Railways, along with the recently developing Chenab Arch Bridge, highlights the engineering marvels of the Indian Railways.

The present Government, under the leadership of Modiiji, is working to maintain the historic heritage of Railways as well as modernise systems for efficiency. Indian

Railway is set to see its highest ever capital expenditure of Rs.2.45 trillion for 2022-23. The grants under the Demands for Grants are welcomed and should be approved. The images of *Vande Bharat* Express trains, Vistadome coaches, airport-standard stations, periodic reports about record-breaking capital investments, historically-high originating freight loading and, thankfully, historically lower number of accidents, etc., are the trending news for the Indian Railways. In this Budget, 400 new-generation *Vande Bharat* trains and 100 PM Gati Shakti Cargo Terminals, to be developed during next three years, are promised. This is going to put India on the global map with reliable infrastructure backbone. These all have been made possible by the untiring efforts of hon. Suresh Prabhuji, hon. Manoj Sinha ji, hon. Piyush Goyal ji and now hon. Ashwini Vaishnaw ji, and all the Ministers associated with Railways and the officers to provide the results with such commitment.

During the trying times of Covid-19, Indian Railways helped in mobilising the life saving oxygen to various parts of India. When our hon. Prime Minister, Modi ji, announced '*PM Garib Kalyan Yojana*', Indian Railways helped in making sure the foodgrains are transported to every nook and corner of the country.

India is one of the major hubs for IT expertise in the world and e-governance is one of the major components where we are looking to enforce governance by leveraging Information and Technology. Indian Railways is an example of ICT (Information, Communication and Technology) and governance working in synchronisation.

Our hon. Minister has made it possible that passengers can directly tell their grievances on WhatsApp and they would get a response from the concerned Department. This bridges the gap between common people and the Government. The passengers can now bring their grievances to social media and their grievances are heard. We have come a long way since 2014 in this regard, where even booking online tickets through IRCTC was a humongous task, and today we not only book the tickets online but we have a medium to track the live status of a train with accuracy.

During 2019-20, around 4,24,000 non-gazetted employees have been provided with different types of training, that is, initial, promotional, refresher, specialised, etc. The railways maintaining one of the largest workforce in the country and training them regularly is certainly a major achievement.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.*]

In the effort for '*Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas*', the system of direct benefit transfer has been developed to provide money directly to the labourer

instead of just the contractors. This talks about the commitment of the Government towards its people. One can check the '*Shramik Kalyan Portal*' to see how Indian railway is ensuring 100 per cent compliance of minimum wage payment with transparency.

Sir, I would like to raise a question regarding the labourer hired by the contractors, and here I would like to draw the attention of the hon. Minister, working for Indian Railways. Is there a mechanism to confirm the identities of these workers? There is information that illegal immigrants are being hired by the contractors to work without any document verification. This could jeopardise the safety of the Indian citizens. We need a mechanism where the labourers are vetted for all their identity documents.

There used to be a time where we would hear about the railway robberies every now and then, but the frequency of theft has decreased. But a lot more efforts are needed as railway protection is the responsibility of Government Railway Police (GRP) and State Police.

Sir, development of high strength rails, upgradation of indigenously-developed ATP (Automatic Train Protection) system, TCAS (Train Collision Avoidance System) Phase-II project having features like interfacing electronic interlocking, centralised traffic control and remote updation of TSR (Temporary Speed Restriction), etc., have been done.

In addition to it, new designs of high horsepower locomotives were developed during this period. Over 350 critical and long-pending major bridge and track works, having bearing on safety and operational efficiency have been carried out, and, backlogs have been cleared. Some of these works were pending for several years and here comes another example like Bogibeel bridge.

Since 2014, train accident cases have reduced but we recently witnessed a major accident in which, at least, nine people died and 36 others were injured after 12 coaches of the Bikaner-Guwahati Express derailed near Mayanaguri in West Bengal's Jalpaiguri District. It was said that a glitch in locomotive equipment led to the mishap. There was also news that the mandatory inspection was not done in the North-Eastern Railway. Everyone should be responsible for everyone's life. Our irresponsibility at any level could cause immeasurable harm to our family.

Sir, we all know that development of railways is a continuous process and we need to read developments in the context of previous Budgets as well. Present Chief Minister of West Bengal had served two terms as Railway Minister. First time in 1999 as part of the NDA Government and second time in 2009 as part of UPA Government.

One of the renowned international news-agency "Reuters" reported, "Her two-year record as Railway Minister has been heavily criticized for running the network into more debt to pay for populist measures such as more passenger trains." The Indian Railways became loss-making organization during her two-year tenure. There were over 100 railway functions inaugurating new projects or for flagging off new trains in West Bengal in the last six months of her tenure as Railway Minister. Most of them did not make much progress. Several Railway projects announced by her during her tenure as the Railway Minister have been sent to the 'Rs. 1000 allocation bracket' by the Central Government at that time. The Railways is a public good and it is the taxpayers money which is used for its development. So, announcements of new railways should be economically justifiable and financially viable. ...(*Time-bell rings*)...

Sir, through you, I would like to narrate an incident to this august House. It is a very happening incident and I am sure, Members would be happy to know about it. ...(*Time-bell rings*)... Sir, it is regarding the undying commitment of Railway employees. An elderly American-Indian couple was travelling from Kolkata to Puri. Somehow, the wife was unable to board the train and they got separated. The purse, ticket, money, ID card and everything else was with his wife in her purse. Before I could talk to the GRP or anyone, the lady went to the GRP and the officers took action on it immediately and the problem was solved before the train reached the next station. I am so happy to see the commitment shown by the people who are working in Indian Railways.

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आप परमिट करें, तो मैं दो-चार चीजें बताना चाहती हूँ। Finally, जब मुझे रेलवे की बात कहनी पड़ती है, whenever I talk about railway, I cannot forget those days, those incidents mentioned by my mother, my father when people fled from then Purba Pakistan to India during partition by train. Sir, only after Modi ji has taken charge, train connectivity between India and Bangladesh has been reinstated. Today, we have four trains running between India and Bangladesh. These are Mitali, Bandhan, Maitree and others. It is such a happy state of affairs. सर, आप allow करें, तो मैं दो-चार छोटी-छोटी रिक्वेस्ट्स करना चाहती हूँ। पश्चिमी मेदिनीपुर में, दांतन में स्टेशन पर जगन्नाथ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका नंबर 18409-18410 है, वह रुकती थी। कटक, भुवनेश्वर में बहुत सारे patients एम्स में जाते थे। वह ट्रेन काफी साल से चल रही है, लेकिन अभी कोविड के बाद वह ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती है।

मेरी एक और रिक्वेस्ट है। बच्चों ने और Visva-Bharati University और बर्दवान यूनिवर्सिटी से लोगों ने रिक्वेस्ट की है, जो हावड़ा-दिल्ली राजधानी वाया गया है - 12301 और 12302, अगर ये बर्दवान में रुकती हैं, तो बीरभूम, बांकुड़ा, बर्दवान जंक्शन, हुगली, मुर्शिदाबाद, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत बड़ा फायदा होगा।

सर, अगर आप मुझे दो मिनट और दें, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। पश्चिमी मेदिनीपुर में Cossye Halt नाम से एक जगह है, वहां पर एक रिवरब्रिज है। वहां 30-35 साल से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत थी। सीपीआई(एम) के समय से उनकी मांग शुरू हुई थी। मैं वहां खुद तीन-चार बार विज़िट करके आई। जब पीयूष गोयल जी थे, तब मैं वहां आई और मनोज जी और पीयूष जी को मैंने पूरी रिपोर्ट दी। मैंने कहा कि मैं एमपीलैड्स से यह कार्य करना चाहती हूं। यह एक छोटा सा प्लेटफॉर्म का कार्य ढाई करोड़ का है। पीयूष जी बोले, नहीं-नहीं, इसमें एमपीलैड्स की क्या जरूरत है, इसको हम कर देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे करने दीजिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप करिए। पूरी रिपोर्ट मंगवाई गई है, उसकी कॉस्टिंग का ब्योरा बन गया है। सर, पश्चिमी बंगाल में चार साल से एक भी डीएम ने मेरा यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। यह काम जनता के लिए है, मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूं, जनता के पैसे से करना चाहती हूं, यह मेरा पैसा नहीं है। मैं आप सभी के द्वारा यह रिक्वेस्ट करती हूं कि डीएम ठीक से काम करें और सभी सरकारी ऑफिसर्स सम्मान के साथ काम करें। मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा रेलवे बजट बनाया है।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, before starting my speech, I would like to compliment the new Railway Minister, Vaishnaw ji. As a Railway Minister, although it is not a separate Budget, this is his first Railway Budget. I must compliment you and am also hopeful of getting good response from you, Sir.

The Budget allocation for the North-Eastern Region is hiked by more than 44 per cent in comparison with the previous Budget. The Budget allocation for the North-Eastern Region is Rs. 11, 428.86 crores. This is all-time high allocation for the North-Eastern Region. I must compliment you for this. Not only that, till today, many a Railway Minister has come and many Railway Budgets have been passed by this Parliament, but for the first time, there is 37 per cent hike in the allotment for the North-Eastern Region. This is also an all-time record, Sir. I compliment you for this also. It is known to everybody that Assam was neglected like anything during the Congress regime. For a single bridge, we had to agitate for a long time. After long agitation, after students started boycotting the classes, after people took part in the *satyagraha*, after people lost their lives in police firings, after all these, we got the bridge during the Congress regime. I am very grateful to the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji. This is the first Government which has seen to it that all the North-Eastern Region of our country has railway connectivity today. This is also an all-time record.

I would now like to raise some issues. One of the major issues which we are facing is, due to lack of electricity, double-track line is not available in Assam and in the North-Eastern Region. Hon. Minister, can you imagine, during these modern

days, there is no electrical train in almost all parts of the North-Eastern Region? Can you imagine there is no double track rail line in the entire region?

I hope under your leadership this time we will get justice. This is the call of the hour.

Sir, I would like to draw your attention to another very important issue. This is in the interest of our sovereignty and national interest. China built railway lines up to Tawang in their area. I would request the hon. Minister to start at least a toy train from Tezpur to Tawang. Tawang is nowadays one of the most popular tourist spots of the country. Whoever has visited Tawang says that it is better than Switzerland. I would request you to please start at least a toy train up to Tawang. Our neighbouring country China built train tracks up to Tawang.

Now the situation is somewhat different. Today, the entire North-Eastern Region has railway connectivity. All the seven States have railway connectivity. But there is not a single coach factory in any part of the North-Eastern Region. I want this gift from our Government. At least start a coach factory in the North-Eastern Region which will fulfill the demand of our area.

One complaint that we get from the common people is this. All the railway wagons in the North-Eastern Region, including those of the Rajdhani Express from Delhi to Guwahati and Dibrugarh, and all the bogies are old. The bogies which are not going to be used in other parts of the country are sent to Assam. This attitude must be censured. We are also good citizens. We are also Indian citizens. This Government is doing a lot of development in the North-Eastern Region. The Prime Minister always pays special attention to the North-Eastern Region. I believe this will be looked after by you.

Sir, a Railway Division is there. Now a separate Railway Zone is required in the North-Eastern Region. All the States of the North-Eastern Region have railway connectivity. There should be a separate Railway Zone in Assam.

According to a report of the World Health Organization, the highest number of cancer patients in India is coming from Assam and Punjab. Daily hundreds of people visit Mumbai for treatment of cancer. On humanitarian ground and in the interest of cancer patients, are you ready to introduce a Duronto train between Guwahati and Mumbai? They will bless you, Sir. This is the call of the hour.

Sir, every day hundreds of people visit Maa Kamakhya Temple. From every part of India, people visit Maa Kamakhya Temple. I would request you to introduce a special train in the name of Maa Kamakhya from Kolkata to Guwahati and from Delhi to Guwahati also.

There are more than 10,000 posts vacant in Grade III and Grade IV in the NF Railway. Unemployment is a big issue. Not just in Assam, but in the whole of North-East, it is a big issue. No industry is there. These vacancies should be filled up immediately. And special attention should be paid to the local people for those appointments.

Sir, I would like to draw your attention to one more issue. Already construction of a railway track has started from Goalpara to Guwahati. But its speed is very slow. Speed is very slow because double track line is not there. So, I would request him to look into this issue immediately and help them.

Sir, historically, Assam is a very famous area. I proudly say that we, the people of Assam, defeated Mughals 17 times. When Mughals attacked all parts of India, Assam defeated Mughals 17 times. They were not allowed to enter Assam. There are various tourist spots. So, I would like to request you to kindly look into this issue and introduce some local train in those areas.

Sir, I would like to say one more thing. There is a town nearby Guwahati; there is no railway connectivity. Hon. Vice-Chairman, Sir, you also know that there is no railway connectivity. There is connectivity up to Mazbat. From Mazbat to Kharupetia, the distance is only 35 kilometres. If you start a railway line from Mazbat to Kharupetia, that entire district and city will get railway connectivity and the people of this region can travel easily to other parts. So, I would request you for that. There is one more thing. You remember that earlier when the Railway Budget was presented, it was announced that there would be two super specialty hospitals -- one at Rangapara and another one at Bongaigaon. This was part of the Union Budget, which was passed by the august House. But this was not implemented. It has not been implemented for the last ten years. At the time of UPA, they announced it. They announced that there will be a super specialty hospital in Bongaigaon; they announced that there will be a super specialty hospital in Rangapara. But nothing has happened. Now, at least, this Government should look into this issue as a promise and an assurance given in the Budget by the Government earlier. Kindly resolve this issue.

At last, I would like to conclude with a request. We, the people of Assam, are very peace loving people. Guwahati is the heart of the North-Eastern Region. Now, North-Eastern Region has railway connectivity. There is a railway line up to Meghalaya; there is a railway line up to Nagaland; there is a railway line up to Arunachal Pradesh. So, I would like to request you to kindly consider these issues in the interest and development of the North-Eastern Region. The hon. Prime Minister has always given utmost importance to the North-Eastern Region. So, in the interest

of the North-Eastern Region, at least, in our time, you should announce one coach factory in the North-Eastern Region. This will be helpful in building infrastructure in those regions and it will help in reducing unemployment. With these words, I thank you and I hope, under your leadership, we would get justice.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : मान्यवर, आपने रेल मंत्रालय के कार्यक्रम पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

आज जब मैं सदन में आ रहा था तो बिहार के बहुत सारे लोग, नौजवान साथी मुझसे घर पर मिलने आये और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। 2019 में उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली गई परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा पास कर ली, मुख्य परीक्षा पास कर ली, चिकित्सा की जांच पास कर ली, लेकिन 2019 से लेकर आज तक, तीन साल हो गये, 8 से 10 हजार नौजवान ऐसे हैं, जिनको नियुक्ति नहीं मिली है, जिनको आज तक joining नहीं मिली है। यह बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। जब वे रेलवे भर्ती से पीड़ित नौजवान छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरते हैं, पटना में सड़कों पर उतरते हैं तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। उन पर आँसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उनको लाठियों से पिटवाते हैं, घर में घुस-घुस कर उनको मरवाते हैं, पिटवाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि वे दुश्मन देश के नागरिक हैं! आप इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया क्या है? मान्यवर, रेलवे में हर जगह ठेका प्रथा चालू कर दी गई है। सफाई कर्मचारियों में ठेका प्रथा, स्टेशंस के maintenance में ठेका प्रथा, सिग्नल के maintenance में ठेका प्रथा, बिजली के maintenance में ठेका प्रथा, कोच के maintenance में ठेका प्रथा। जब आप ठेका प्रथा लेकर आ रहे हैं, तो एक तरफ आप रोजगार को मिटाने और खत्म करने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आरक्षण की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, आप उनका हक मारने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, खुद रेलवे विभाग ने यह माना है कि safety category में लगभग 1 लाख, 50 हजार कर्मचारियों की vacancies हैं। आपके पास लगभग 1 लाख, 50 हजार रिक्तियाँ सिर्फ safety category में हैं, रेलवे की सुरक्षा के क्षेत्र में हैं। आप वह भर्ती करते नहीं हैं। आपके पास maintenance के क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में रेलवे में पद खाली हैं, वहाँ पर आप भर्ती क्यों नहीं करते हैं? अगर रेलवे विभाग चाहे, तो वह 3 लाख पक्के सरकारी कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है, लेकिन आपको पिछड़ों का हक मारना है, दलितों का हक मारना है, निजीकरण करना है, सरकारी व्यवस्था को खत्म करना है। मान्यवर, हमारे मंत्री जी ने बयान दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इन्होंने कहा कि निजीकरण नहीं होगा। अब पता नहीं वित्त मंत्री और रेल मंत्री एक साथ बैठते हैं कि नहीं, दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं कि नहीं, वित्त मंत्री जी कहती हैं कि हम रेलवे की 26 प्रतिशत संपत्तियाँ बेचेंगे, हम रेल की संपत्ति बेच कर लगभग 1 लाख, 50 हजार करोड़ रुपए अर्जित करने का काम करेंगे। मेरे पास तारीख है, इन्होंने 31 हजार करोड़ रुपए का टेंडर निकाला, जिसमें से इनको मात्र 7 हजार, 2 सौ करोड़ रुपए की आय हुई, बाकी लोगों ने टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया। एक तरफ आप लोगों के बीच में तो यह

कहते हैं कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन आप रेलवे के अंदर निजीकरण करने के लिए जितनी भी योजनाएँ ला सकते हैं, उन्हें लाने का काम करते हैं।

मान्यवर, दूसरी बात, मैं पढ़ रहा था कि रेलवे में पिछले 5 वर्षों से लगातार आमदनी में कमी आ रही है। इनकी आमदनी लगभग 7.8 प्रतिशत घटी है। रेलवे की आमदनी भले ही घट रही हो, भले ही आपने पिछले दिनों में रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपए कर दी हो, पैसेंजर के किराए में आपने 3 गुनी वृद्धि कर दी हो, बाकी चीजों में वृद्धि कर दी हो, लेकिन आपकी आमदनी 7.8 प्रतिशत घटी। आप ये आँकड़े बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे को घाटा पहुँचाने के लिए तैयार रहते हैं, आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे का नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ। हमारी दिल्ली की सरकार बुजुर्गों के लिए 'तीर्थ यात्रा योजना' लेकर आई। अब उन बुजुर्गों के लिए 'तीर्थ यात्रा योजना' से आपको क्या परहेज है! बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने से आपको परहेज है। यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री इसी दिल्ली में उन बुजुर्ग यात्रियों से स्टेशन पर मिलने जा रहे थे। रेलवे विभाग ने उन बुजुर्गों से उनकी मुलाकात को रोकने का काम किया। मंत्री जी, आप IAS रहे हैं, जिला अधिकारी रहे हैं, ओडिशा में आप IAS के तौर पर नौकरी कर चुके हैं, आप एक मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए। मैंने आपको पच्चीसों फोन किए, पच्चीसों बार मैंने आपके विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी, मुख्यमंत्री के आवास से आपको सूचना गई, लेकिन आप बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को अयोध्या जाने से रोकने का काम कर रहे हैं, आप उनकी तीर्थ यात्रा पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़नी है, तो चुनाव में लड़िए न! आप बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को क्यों target करते हैं, आप उनकी यात्रा का विरोध क्यों करते हैं! आप रेलवे की आमदनी कम करने पर क्यों लगे हुए हैं! आप अरविंद केजरीवाल का इतने हद तक जाकर विरोध क्यों करते हैं! आप चुनाव लड़िए न! चुनाव से तो आप लोग भागते हैं। MCD का चुनाव हो रहा है, लेकिन आप लोग भाग रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप लोग भाग रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ये MCD के चुनाव से भाग रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... **...(समय की घंटी)**... मैं खत्म कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... हिम्मत है तो चुनाव लड़िए। ...**(व्यवधान)**... आप भागते क्यों हैं? ...**(व्यवधान)**... * ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You address the Chair. ...*(Interruptions)*... Hon. Member. ...*(Interruptions)*... Hon. Member, please address the Chair. ...*(Interruptions)*... You don't have to answer them. ...*(Interruptions)*... You address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह : मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ, तीन बार दिल्ली में इनकी जमानत जब्त हो गई है। एक बार ये स्कूटर पार्टी बन गए, इनकी सिर्फ तीन सीटें आईं, दूसरी बार इनोवा पार्टी बन गए,

* Expunged as ordered by the Chair.

सिर्फ आठ सीटें आईं। ये पिछली तीन बार से हार रहे हैं और अब ये एमसीडी के चुनावों से भाग रहे हैं।...(व्यवधान)... ये कह रहे हैं कि हम अरविन्द केजरीवाल का सामना नहीं कर सकते।...(व्यवधान)... आप लोग चुनावों से इतने डरते हैं। ...(व्यवधान)... आप लोग देश के प्रधान मंत्री जी की छवि खराब कर रहे हैं। देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।...(व्यवधान)... दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एमसीडी के चुनावों से भाग रही है और केजरीवाल से डर रही है।...(व्यवधान)... * मैं कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : धन्यवाद।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, यह बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)... रेल मंत्री जी, हम लोग सांसद हैं, हम आपके पास कोई हमेशा पैरवी करवाने के लिए नहीं आते हैं और न ही आपको रोज़-रोज़ फोन करते हैं।...(व्यवधान)... लेकिन अगर हमारे निर्वाचित मुख्य मंत्री जी को आपका रेलवे विभाग अपमानित करेगा,...(व्यवधान)... हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप फोन पर भी नहीं आएंगे और मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देंगे, आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है।...(व्यवधान)... यह बहुत ही दुखद व्यवहार है।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : धन्यवाद।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : आपको दिल्ली की सरकार मुनाफ़ा देती है।...(व्यवधान)... दिल्ली की सरकार रेलवे से तीर्थ यात्रा करवाती है और आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have made your point. ...*(Interruptions)*... धन्यवाद, आपका समय खत्म हो चुका है।

श्री संजय सिंह : सर, एक अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सर, अभी दूसरों को तो आपने 12-12 मिनट का समय दिया था, लेकिन जब हमारी बारी आती है, तो उधर से वे लोग चिल्लाने लगते हैं और इधर आप भी रोकने लगते हैं। ...(व्यवधान)... हमेशा यही होता है।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आपकी पार्टी के पास जितना समय होता है, हम उसी के अनुसार बुलाते हैं।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : वहां वे लोग चुनाव से भागते हैं और यहां आप बोलने नहीं देते! ...(व्यवधान)...

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप कन्क्लूड कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : * तो हम लोग कहां बोलें? ...(व्यवधान)... हम लोग अपनी बात कहने के लिए कहां जाएं? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप रेल बजट पर बोलिए, पूरे भाषण में आप रेल बजट पर तो बोले ही नहीं।...(व्यवधान)... आप कन्क्लूड कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : सर, रेल बजट पर फिल्मी दुनिया तक की बातें हो गईं।...(व्यवधान)... अभी ये लोग रेल बजट पर फिल्म के गीत गा रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं, रेल मंत्री जी, आप बुजुर्गों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता लाइए।...(व्यवधान)... आपने रेलवे में बुजुर्गों को दिया जाने वाला कंसेशन खत्म कर दिया, आप थोड़ी संवेदनशीलता लाइए। लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे, तो उन्होंने कुलियों को नौकरी देने के लिए योजना लागू की थी।...(व्यवधान)... सर, देखिए, अब ये लोग कुलियों का भी विरोध कर रहे हैं।...(व्यवधान)... ये लोग कुलियों का भी विरोध कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप अब अपनी बात खत्म कीजिए, आपका समय समाप्त हो चुका है।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : ये लोग गरीब आदमियों का विरोध कर रहे हैं।...(व्यवधान)... ये लोग 'सबका साथ-सबका विकास' की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद महंगाई बढ़ा रहे हैं।...(व्यवधान)... ये सिलेंडर के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं और जब हम यहां कुलियों की बात बोलते हैं, तो ये उसका विरोध करते हैं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : धन्यवाद, आपके सारे प्वाइंट्स खत्म हो चुके हैं, आप कन्क्लूड कीजिए।...(व्यवधान)... अब आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : सर, देश के पूर्व रेल मंत्री ने इस देश के कुलियों के लिए काम किया था, जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म में एक गाना था, 'सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।'...(व्यवधान)... उन बोझ उठाने वालों के लिए देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने नौकरी देने की व्यवस्था की थी।...(व्यवधान)... आज वे मारे मारे फिर रहे हैं।...(व्यवधान)... वे ऐप्लीकेशन देते हैं, रोते हैं, धक्के खाते हैं, लेकिन उनकी बात आप नहीं सुनते।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, the next speaker is Shri Jawhar Sircar. ...*(Interruptions)*...

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय सिंह : आप इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Jawhar Sircarji, do you want to speak? ...**(Interruptions)**...

श्री संजय सिंह : * ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): This is not done. ...**(Interruptions)**... Please. ...**(Interruptions)**... The next speaker is Shri Jawhar Sircar...**(Interruptions)**... I have called the next speaker. ...**(Interruptions)**... नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होती है, please be seated. ...**(Interruptions)**... आपका समय खत्म हो चुका है, Jawhar Sircarji, do you want to speak? ...**(Interruptions)**... Please. ...**(Interruptions)**... आपका समय खत्म हो चुका है, आप अब जवाहर सरकार जी का टाइम ले रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... जवाहर सरकार जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... If you do not want to speak, I will call the other speaker. ...**(Interruptions)**... No; no, this is not the way. ...**(Interruptions)**... जवाहर सरकार जी, क्या आप बोलेंगे? Nothing will go on record except Shri Jawhar Sircar. ...**(Interruptions)**... Nothing will go on record except Shri Jawhar Sircar. ...**(Interruptions)**...

श्री संजय सिंह : #

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Sir, I thank you for this opportunity ...**(Interruptions)**... Sir, I thank you for this opportunity to make just a few short points on the Railway Budget. ...**(Interruptions)**... The first thing that I would like to draw the hon. Railway Minister's attention...**(Interruptions)**... आप मेरा समय क्यों बरबाद कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप बोलिये, आपकी बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

SHRI JAWHAR SIRCAR: The first thing that I would like to draw the attention of the hon. Railway Minister, who has a wide background of administration, is that half the railway passengers in India on a daily-basis are just from three suburban railways. The three suburban railways constitute half the daily passengers of India. With this in

* Expunged as ordered by the Chair.

Not recorded.

mind, if half the passengers or even 45 per cent of the passengers are the suburban passengers of Mumbai, Kolkata, Chennai, they have never got even one per cent of the Railway Budget. They go packed like animals, they hang out like bats. This sort of a shameful treatment of suburban railway passengers must end during your tenure, Mr. Railway Minister. You can take a look at that. That is the first point I am making that suburban railways have always been neglected, except in very brief periods.

So please look at suburban railways as a special project. The problem is, though he has some of the finest cadres of traffic, accounts, mechanical, electrical, the finest cadres, yet most of them consider suburban railways to be a pain, to be unprofitable. Now you cannot have profitability everywhere. We don't have profitability in MGNREGA. We don't have profitability in 'Food for Work', in food aid. So, treat it as a social sector project. My first request is, you will be catering, in one stroke, to 50 per cent of the daily passengers of India. Please take a fresh look at it.

The second point I would like to make is NMP. The National Monetization Pipeline scheme is a cloud wrapped within an enigma, wrapped within a mystery. Please come out transparently. Railways are too important and too risky to be leased out, even for a short while, to private profiteers. You are talking of leasing 1,400 kms. I cannot travel in a Rajdhani wondering whether the next 100 kms. of tracks are being maintained by a profiteer. Please, please clarify, where you are doing it, on what grounds you are doing it. Every feet of railway line has to be maintained and the Railways are doing a splendid job out of it, but in spite of that, accidents happen. So please be careful; Railways are the lifeline of India. Before you lease out anything of the railways, please be more transparent. Let it be in the public domain. Your Budget is Rs.1.5 lakh crores. Your net worth is more than the Government of India's Budget. You are an aristocratic department, come out transparently. Don't play behind screens.

So my second point is on NMP. You are leasing out 400 stations. Which 400 stations? Who is in-charge of what? Who is in-charge of signaling? Who is in-charge of delays? Who is in-charge of other things? The Railways are the heart of the administration of India. Do not play around with it. If you have to lease, if you have to earn money, build supermarkets over railway stations of urban areas which is within your control. It is not like a gas pipeline from one end to the other that you lease out. Railways are just too risky. So before we fall for this NMP game, which is, as I said, an enigma and within a mystery within another mystery, so please come out with facts. One of the hon. Members has said a lot of negative things about Ms. Mamata Banerjee as Railway Minister. I don't want to get into all that.

All I am saying is that she had a vision statement made by professionals when she was here. The second is that she knows what the people want. Otherwise, she could not be getting elected again and again. Have a look at that statement! Last point that I would like to make is that when you lease out, you are leasing out the pride of India, the Heritage Railways. The Heritage Railways are like the jewels of India. How you can lease out your own jewels, the Darjeeling Railways! First of all, it is under sad state of neglect. वो क्या मेरे सपनों की रानी and all that. It is in a sad state of neglect as it is. What will a private company do there! It requires infrastructural investment. So, you lease out jewels like the Darjeeling heritage Railway, Shimla heritage Railway, even the Konkan Railway, which is one of the pride of the Indian Railways. Why are you going in for that? This * about earning Rupees Six lakh crores from this and that can come about, but not from selling off family silver. Don't sell off our lives, our safety, and our lifeline for a few coins of silver, Mr. Minister. And, my ultimate point, Sir, I won't encroach on your time. One fact is not told to you and to most people. There are many people who require a small machine to be plugged in while travelling on the train, for breathing, CPAP, BiPAP; somebody also mentioned 'bronchial', I think Vasan *saheb* mentioned. So, there are the machines which need very low power consumption. Your Ministry cuts off the electric line every half-an-hour, which destroys the machines. Your light is on, your fan is on; why can't that plug point be on? I mean, I have not been able to understand. I spoke to half-a-dozen people. So, please remember these points that the life-saving point which is just a plug point in your compartment, let it be on. I wound up by complementing you. You come with a wide experience.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Your part of the Budget is good. But, please come back to suburban passengers who are being treated like second-class, third-class citizens and animals. Please reconsider your part in the National Monetization Pipeline. Please reconsider the Heritage Railways. Thank you very much and bless you.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं जो भाषण सुन रहा था, विशेष रूप से दिल्ली के हमारे सांसद श्री संजय सिंह जी का और उसके पहले श्रीमान देरेक ओब्राईन जी का। संजय सिंह जी का भाषण बड़ा विनम्रतापूर्वक होता है, तो भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वे ऐसी ऊँची-ऊँची आवाज़ में बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे और जब ओब्राईन साहब बोलते हैं, वैसे वे एक

* Expunged as ordered by the Chair.

बहुत नवाज़े गए quiz master हैं, उनका सामान्य भाषण भी बड़ा नाटकपूर्ण लगता है, नाटकीय लगता है। हम नाटकीय बोलते हैं, तो भी वह सामान्य लगता है और वे सामान्य बोलते हैं, तब भी वह बड़ा नाटकीय लगता है। वे इस अंदाज़ में बोल रहे थे कि देखो, हमारे पास big ideas थे, यह big idea, यह big idea. यह दीवार फिल्म का जो dialogue है, वैसे ही लगा कि हमारे पास यह है, यह है, तुम्हारे पास क्या है? मैं कहूँगा कि हाँ, ठीक है, आपके पास ideas हैं और हमारे पास implementation है। Ideas का implementation कैसे करना है, हम इसका तौर-तरीका जानते हैं और शायद big ideas, when they are attempted by persons with small minds, I think they never get implemented. यहाँ पर बात उल्टी है, इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहूँगा कि कई सारे big ideas, शायद उसको हम big ideas के स्तंभ के नीचे नहीं गिना पाएँगे। छोटी-छाटी बातें होती हैं, मगर जब लोगों को राहत देने की प्रामाणिक कोशिश होती है, तब उसके परिणाम जमीन पर निकल कर आते हैं, हमें दिखाई देते हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा। हमारे देश में किसानों के बारे में और किसानों को न्याय देने के संदर्भ में बहुत सारी लंबी-लंबी चर्चाएँ हुई हैं, मगर एक स्पेशल किसान ट्रेन का प्रावधान किया जाए, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, यह केवल मात्र मोदी जी की सरकार में हो पाया और आज स्थिति यह है कि देश के चाहे उत्तर भारत के किसान हों, चाहे दक्षिण भारत के किसान हों, चाहे हमारे महाराष्ट्र में जो बागवानी करने वाले किसान हैं, वे किसान हों, आज ये सारे किसान रेल पर निर्भर हैं। आज यहाँ तक है कि किसान रेल से माल भेजने के लिए लगभग दो-दो महीने की वेटिंग लिस्ट है। किसान ट्रेन की संकल्पना को इतना response मिल रहा है।

It may not be a big idea, perhaps, envisioned by some people, but, certainly a big idea in the sense that the idea got implemented with all political will.

दूसरी बात, हम देखते थे कि रेलवे स्टेशंस के किनारे जाते समय, ट्रेक्स के आस-पास, चूँकि मैं मुम्बई से आता हूँ, इसलिए कई बार ट्रेक्स के आस-पास से गुजरना भी पड़ता है, वहाँ लोगों को अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए जाना पड़ता था। हम ट्रेनों में भी देखते थे कि सामान्य यात्रियों के जो कोचेज़ होते हैं या जो स्लीपर कोचेज़ होते हैं, उनमें साफ-सफाई वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज मैं विपक्ष के हमारे सभी मित्रों से भी कहूँगा कि आप कभी सामान्य कोच में स्लीपर क्लास में travel करिए, वहाँ पर भी दो-दो बार सफाई वाला आता है और पूछता है कि कहीं कुछ गंदगी है, तो आप हमें बताइए, हम साफ कर रहे हैं। इसके साथ ही, बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। यह छोटा सा विषय है। It may not be a big idea, what Mr. Derek O'Brien wanted to describe, but, it is a small attempt, a sincere attempt which has a big impact and therefore, बायो-टॉयलेट की व्यवस्था भी बड़ी कारगर साबित हो गई है। मैं यह विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ।

महोदय, कई लोग जानते हैं कि रेलवे की भी अपनी एक दुनिया होती है और रेलवे की दुनिया में रेलवे के लोगों के टेलिफोन्स अलग हैं, रेलवे के लोगों के काम करने की पद्धति अलग है। उनकी अपनी एक अलग व्यवस्था रहती है और उसी व्यवस्था के चलते, जिसे सामंतशाही का प्रतीक माना गया था, ऐसे ही एक Railway saloon की व्यवस्था थी। जब बड़े-बड़े अधिकारी जाते थे, मंत्री जाते थे, उनके लिए बड़े शाही कोचेज़ में जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने किसी समाजवाद वगैरह का विषय उठाए बगैर saloon की बादशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।

हमारे मंत्री भी सामान्य कोच से जाते हैं, हमारे बाकी लोग भी सामान्य कोच से जाते हैं। मैं मानता हूँ कि जब हम एक संवेदना दिखाते हुए चीजों को अमल में लाते हैं, तब क्या होता है, यह इसका एक परिचायक है।

महोदय, हमने दीनदयालु कोच बनाए और सामान्य यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं भी कीं। हमने देखा कि हमारे यहाँ जो कोचेज़ बनते थे, पहले एक ज़माना ऐसा था कि हमें जर्मन कोचेज़ आयात करने पड़ते थे, लेकिन आज यह स्थिति है कि पड़ोसी देशों में कई ऐसे देश हैं, जहाँ हम भारतीय रेल की कार्यशालाओं में बने हुए कोचेज़ निर्यात कर रहे हैं और इसका पूरी दुनिया में स्वागत हो रहा है।

महोदय, मैं कुछ और बातें भी कहूँगा। यहाँ पर माल ढोने की व्यवस्था पर चर्चा हुई। मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के कुल मिलाकर सात साल के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण परिचायक रहा है कि हमने dedicated freight corridor को महत्व दिया और आज ऐसे corridors के कारण माल की ढुलाई बहुत आसानी से हो रही है, बहुत तीव्र गति से हो रही है। इसी तरह से, हम विद्युतीकरण के बारे में भी कह सकते हैं। रेलवे का जिस पद्धति और तेजी से विद्युतीकरण हुआ है, मैं उसके आंकड़े देना चाहता हूँ। 2014 से 2021 के दौरान प्रति वर्ष रेलवे विद्युतीकरण की गति को 5.5 times अधिक बढ़ाया गया है। 2009 से 2014 के कार्यकाल में, उस समय यूपीए की सरकार थी, तब रेलवे विद्युतीकरण 608 किलोमीटर प्रति वर्ष था और आज 2014 से 2021 के साथ इसकी तुलना करें, तो यह 3,440 किलोमीटर प्रति वर्ष है। मैं मानता हूँ कि हम इस वास्तविकता की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से, मैंने यहाँ पर DFC का भी ज़िक्र किया कि इससे हमारी क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है और किस पद्धति से हमारे manufacturing sector को इसका लाभ हुआ है।

महोदय, मैं स्पोर्ट्स के विषय में भी कहना चाहूँगा। जब हम रेलवे के कुल योगदान की चर्चा करते हैं, तब कई बार इन बातों को भूल जाते हैं कि रेलवे ने हमारे कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को किस पद्धति से प्रश्रय दिया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है, अतः मैं मानता हूँ कि रेलवे का इस विषय में भी एक योगदान है।

महोदय, अगर हम विगत कुछ सालों को, विशेष रूप से 2009 से 2014 को देखेंगे, तो पाएंगे कि दोहरीकरण और gauge conversion का जितना काम हुआ था, विगत सात सालों में उससे 66 परसेंट अधिक काम हुआ है। अगर हम सिक्किम को छोड़ दें, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि हम इस बात की भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, तो मैं रेल विकास निगम के बारे में बताना चाहूँगा। जब से उसका आईपीओ आया है, तब से वह रेल विकास निगम, जो एक समय घाटे में जा रहा था, आज मुनाफे में आ गया है।

4.00 PM

इतना ही नहीं, हम सामाजिक संवेदना के आधार पर काम करते हैं। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि रेलवे का एक नियम है कि अपवाद को छोड़ते हुए सामान्यतः रेलवे स्टेशंस

को व्यक्तियों के नाम नहीं देते, मगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एक बार हमने अपवाद किया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की एक स्वर में यह डिमांड थी कि कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को छत्रपति साहूजी महाराज का नाम दिया जाए। हमने अपवाद किया और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को छत्रपति साहूजी महाराज स्टेशन का नाम दिया। ...**(समय की घंटी)**... उसी तरीके से, अभी भोपाल के निकट हबीबगंज का जो नया स्टेशन बना है, उसका नाम उपेक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली रानी कमलापति के नाम पर दिया गया है। हमने अपवाद किए हैं, क्योंकि उपेक्षित नेताओं का सम्मान करना जरूरी है। इस विषय की एक प्रतिबद्धता होने के कारण हम काम करते हैं।

महोदय, मैं मुम्बई से आता हूँ और मुम्बई तथा महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का विषय एक बड़ी चर्चा का विषय बनता है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन के विषय में बहुत अच्छी तरक्की हुई है, जिसके कारण रोजगार का सृजन हो रहा है। विशेष रूप से, गुजरात में 99 परसेंट acquisition of land हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में जितना काम होना था, उसका 20 प्रतिशत काम भी अभी तक नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि हम federalism की बात करते हैं, मगर इस पद्धति से अगर एक प्रोजेक्ट को हम अधर में लटका देंगे, तो यह महाराष्ट्र की जनता पर घोर अन्याय होगा। मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता इस पद्धति की अकर्मण्यता को कभी माफ नहीं करेगी। अभी अहमदाबाद से वापी तक 650 पिलर्स लग गए हैं। बुलेट ट्रेन का काम 8 किलोमीटर प्रति माह के हिसाब से चल रहा है, मगर दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र से जो प्रतिशत आना चाहिए, जो response मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मैं सदन को इस विषय के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ। महोदय, मैं पाँच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। मुझे बताया गया था कि 10-15 मिनट बोलना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : मिनिस्टर साहब को लोक सभा जाना होगा, क्योंकि वहाँ गिलोटिन है। ...**(व्यवधान)**...

DR. VINAY P. SAHASRABUDHE: I will just finish in five minutes. I am giving bulleted suggestions and nothing more than that.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : यह हो नहीं पाएगा। ...**(व्यवधान)**...

DR. VINAY P. SAHASRABUDHE: Can you give me just minutes? ...**(Interruptions)**... I will finish in two minutes. ...**(Interruptions)**..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please finish in two minutes.

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे : सर, मुख्य रूप से मेरे दो सजेसंस हैं। रेलवे की प्रतिस्पर्धा हवाई यातायात से भी है, क्योंकि प्रधान मंत्री जी के जमाने में अभी हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई

यातायात का प्रयोग करने लगे हैं। रेलवे को एक ओर हवाई यातायात से भी प्रतिस्पर्धा करनी है और दूसरी ओर निजी मार्ग परिवहन से भी प्रतिस्पर्धा करनी है। मेरा सुझाव है कि रेलवे को overnight trains पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना overnight distance है, उसको कवर करने के लिए लोग रेल का ज्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि उसमें कार से जाना मुश्किल है और वायुयान से जाना कई बार affordable नहीं होता। उस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि हमारे जो स्लीपर क्लास के यात्री हैं, स्लीपर क्लास में जो 72 berths होती हैं, आप चाहे उनसे दो-पांच रुपये अधिक लीजिए, मगर हर sleeper class के लिए अगर एक coach conductor होगा, तो sleeper class के यात्रियों के लिए सुरक्षापूर्वक यात्रा करना संभव हो जाएगा। आज एक कोच में एक भी coach attendant नहीं होता, जिसके कारण यात्रियों में असुरक्षा का एक भाव रहता है, उनके मन में डर रहता है कि बीच में कहीं कोई पेपर डालकर सोएगा तो नहीं या मेरे सामान की चोरी तो नहीं होगी? मैं मानता हूँ कि इसके लिए हर sleeper coach में एक coach attendant रखे जाने की व्यवस्था करने के विषय में जरूर सोचा जाना चाहिए।

मान्यवर, मुम्बई के दो-तीन विषय हैं। मैं ठाणे से आता हूँ। मेरा आग्रह है कि ठाणे से बोरीवली के लिए अगर आप एक ट्रेन के बारे में सोचते हैं, चाहे वह हार्बर लाइन से हो या वह वसई के माध्यम से हो, तो अच्छा होगा, क्योंकि ठाणे से बोरीवली सड़क मार्ग से जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए रेलवे इस विषय में जरूर सोचे। आपने 6th corridor बनाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूँगा कि यह बहुत ज़माने से एक प्रलम्बित काम था, जिसे आपने प्रधान मंत्री मोदी जी के कार्यकाल में पूरा कर दिया। मैं मानता हूँ कि उसके कारण लोकल ट्रेन की frequency बढ़ाने की दृष्टि से आप जरूर कोशिश करें। आपने एसी लोकल ट्रेन्स शुरू की हैं, उसकी एक बार समीक्षा की जाए। मेरा यह भी आग्रह है कि दिव्यांगों के लिए लोकल ट्रेन्स में जो कोचेज़ रहते हैं, क्या उनको हम ऐसे senior citizens, जो 75 प्लस आयु के हैं, उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं? इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। यहाँ कई तरीके की बातें हुईं, कुलियों का विषय आया। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूँ कि मुम्बई के स्टेशंस पर बड़ी संख्या में shoeshine boys काम करते हैं, उनके लिए भी अगर हम इंश्योरेंस या स्वास्थ्य के बारे में कुछ चिन्ता कर सकते हैं, तो उपयुक्त होगा। इतना ही कहते हुए और रेल मंत्री जी को साधुवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज कहीं और व्यस्तता रहने के कारण मैंने बार-बार समय बदलने का आग्रह किया था, आपने तसदीक की, सहमति जताई, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारे सभी साथी जानते हैं कि हमारे लिए इस देश में रेल महज़ वित्तीय इकाई नहीं है, वह सिर्फ परिवहन का एक साधन ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक इकाई है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे बचपन से अगर ट्रेन को निकाल दिया जाए, हमारी युवावस्था से ट्रेन को निकाल दिया जाए और हमारे प्रौढ़ जीवन से भी अगर ट्रेन को निकाल दिया जाए तो मेरा मानना है कि हमारी कई सारी कहानियां अधूरी रह जाएंगी। हममें से कई लोगों ने, लगभग सभी ने ट्रेन के साधारण दर्जे में खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए कई सपने देखे होंगे, उनमें से कुछ

मुकम्मल हुए होंगे, कुछ मुकम्मल नहीं हुए होंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि पाकीज़ा फिल्म में अगर उस गाने - 'चलते-चलते, यूँ ही कोई मिल गया था' ...(व्यवधान)... अगर ट्रेन का वह symbolism निकाल दिया जाए तो उस फिल्म में ट्रेन के माध्यम से विरह और वस्ल की, हिज़्र-ओ-विसाल की कितनी सारी चीज़ें हैं और कई सारी फिल्में बनी हैं। महोदय, यह मैंने इसलिए कहा है कि जब भारतीय रेल पर खतरा मंडरा रहा है - माननीय मंत्री जी बहुत ही कुशल प्रबंधक माने जाते हैं, उनका एक शालीन व्यक्तित्व भी है, लेकिन अकसर ऐसे ही लोगों के माध्यम से कुछ वैसे भी काम करवा लिए जाते हैं, जिनका हमें अंदेशा होता है। मैं और क्या कहूँ! अकसर कत्ल करने वाले हाथ अपने ही होते हैं! ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। वे एक रेल मंत्री के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके दल का हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आज dedicated freight corridor की बात हो रही है, पहला concept note evolved form में उसी वक्त आया। आप रेल नेटवर्क को ले लीजिए और मैं समझता हूँ कि passengers amenities को लेकर उनकी जो पहल थी, कुलियों के absorption को लेकर जो पहल थी - मैं आज यह सब थोड़ी पीड़ा में कह रहा हूँ - एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्य मंत्री रहा, इस देश का रेल मंत्री रहा, जिसने बहुत सारी चीज़ें कीं, तो मैं समझता हूँ कि आज यदि उनको बेहतर चिकित्सकीय हस्तक्षेप की ज़रूरत है, तो वह उनको राग-द्वेष से परे उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि राग-द्वेष से पीड़ा होती है और कष्ट होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं दो-चार सवाल रखूँ, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जैसा अभी हमारे मित्र नीरज शेखर जी ने बलिया के बारे में कहा। महोदय, हो सकता है कि बलिया एक छोटी जगह हो, लेकिन ऐसी जगहों का मिजाज़ बहुत बड़ा है, यूँ ही उसे बागी बलिया नहीं कहा गया। बलिया से हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी आते थे। मंत्री महोदय, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि बलिया के सौंदर्यीकरण में वहाँ स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी की एक आदमकद प्रतिमा लगायी जाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने उस सदन में कई बार कहा था कि अगर मेरे देश की एक बड़ी आबादी और कई सारे नेता एक ऐसे दृष्टिकोण से सोचने लगे, जो मुझे देश हित में नहीं लगता है, तो मैं उस हवा, प्रचंड लहर के बावजूद अपने आत्मबल के आधार पर खुद बना रहना चाहूँगा। आज के दौर में उस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है, कम से कम वह प्रतिमा एक संदेश देगी। उसी तरह बिहार के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी - पूरा बिहार उनका कार्य क्षेत्र था, पूरा उत्तर भारत कार्य क्षेत्र था, मैंने अपनी कमेटी मीटिंग में भी कहा कि समस्तीपुर जंक्शन में उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगायी जाए। महोदय, नीरज भाई ने बकुल्हा को लेकर एक बात कही थी कि उसका नाम जयप्रकाश जी के नाम पर रखा जाए। मैं समझता हूँ कि सदन एकमत हो, वहाँ भी बकुल्हा, Sitab Diara के संबंध में ऐसा संदेश जाए कि ये जो हमारे हीरो थे, हम इनके बारे में सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, बल्कि कुछ करने की भी सोचते हैं।

उपसभापति महोदय, हाल के दिनों में हम लोगों ने visuals देखे होंगे, अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी हुआ, सबने विरोध प्रकट किया, सत्तापक्ष के भी कुछ लोगों ने अलग-अलग ढंग से जीरो ऑवर में अपनी बातें रखीं। माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूँ कि देश को उस तरह के visuals फिर

से न देखने पड़ें, आप यह तय कीजिए। मैं उसकी technicality पर बाद में आऊंगा, लेकिन अभी यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में assistant loco pilot and technician की vacancy निकली, उसके चार-चार एग्जाम हुए, मेडिकल भी हुआ और अभी तक 7,000 अभ्यर्थी stand by में हैं।

सर, आपकी कैटेगरी में वे stand by में हैं, लेकिन उनके ज़ेहन में stand by नहीं है। वे अंदर से हिले पड़े हैं और वे अभ्यर्थी नहीं हैं, परिवार के परिवार हैं। मैं समझता हूं कि इस पर माननीय रेल मंत्री जी की तवज्जो हो। मैं हल्के में एक बात कहना चाहता हूं। मैं तकरीबन 15-16 वर्ष का था, उस वक्त से मेरे शहर सहरसा में ओवरब्रिज बनाने की बात होती थी। उस समय मैंने स्कूल भी खत्म नहीं किया था। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद उस ओवरब्रिज पर कुछ चर्चा चल रही है। माननीय मंत्री जी, आप केवल नोट कर लीजिए कि सहरसा शहर में एक बाज़ार हुआ करता था। इस ओवरब्रिज के खास डिज़ाइन को फॉलो करने की वजह से वह बाज़ार खत्म हो जाएगा, जिससे हज़ारों परिवार तबाह हो जाएंगे और सहरसा शहर की नैसर्गिक पहचान को भी चोट लगेगी। मैं आग्रह करता हूं कि अगर संभव हो, तो एक बार उसके वैकल्पिक डिज़ाइन को दिखवा लीजिए। सर, मैं freight services की बात करता हूं। रेलवे का 85 परसेंट रेवेन्यू इससे आता है, इससे कोई इंकार नहीं है। अगर उसका भी एक composition देखें, तो खास तौर से तीन चीज़ें हैं - coal, iron and cement - 70 per cent. इसमें कितना diversification हो सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। यह आलोचना नहीं है, सुझाव की शक्ति में है।

दूसरा, सन् 1951-52 में रेलवे का 85 परसेंट contribution in carriage था। वर्ष 2019-20 के डेटा के हिसाब से 70.5 परसेंट है। अभी सहरस्रबुद्धे जी यह कह रहे थे कि अभी भी हमारे disabled-friendly goals पूरे नहीं हुए हैं। मैं employment के बारे में कह चुका हूं। सर, आपके पास vacancies हैं, बल्कि across the Railway Zones...(समय की घंटी)... मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। Across the Railway Zones, आपके पास vacancies हैं। आप कई जोन्स में vacancies surrender क्यों कर रहे हैं?

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

सर, एक देश में, जहां unemployment आज इस चरम परिस्थिति में है, वहां vacancies surrender करना मैं एक बहुत बड़ा गुनाह मानता हूं। मैं जानता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी, कम-से-कम आप इस गुनाह को नहीं करना चाहेंगे। आप उनके लिए दरवाज़े खोल दीजिए। कई बार यहां स्पोर्ट्स कैटेगरी के बारे में चर्चा हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी Scouts and Guides की बात की। वे बच्चे काफी शिदत से, काफी मेहनत से काम कर रहे थे। अभी दो-तीन वर्षों में उनकी भर्ती पर रोक लगी हुई है। मैंने पहले भी एक विषय उठाया था। रेलवे में sanitation workers employ किए जाते हैं, you would be ashamed to know, Sir -- and maybe we have got used to it -- that large scale manual scavenging takes place in the Railways. Their biggest employer is the Railways.

Finally, Sir, I would like to make a couple of points, in fact, as a matter of suggestion, to the hon. Railway Minister. All your completed work must be audited by an outside agency like the CAG. When I say this, I have some instances to show where this is not being adhered to. There should be expeditious ways to monitor the railway resources, the primary being land, but when you do it, we should also look at the possibilities of using certain part of it for the rehabilitation of vulnerable groups.

Sir, the role and responsibility of RPF and GRP must be re-evaluated, re-visited, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ज़ोन्स हैं, grey areas हैं, जहां हमारी पहल की जरूरत होगी। Sir, in this era of austerity and cost cutting. कई बार चर्चा होती है कि हमें सादगी लानी चाहिए, बहुत खर्चा हो रहा है। Why do we really need a newly created full-fledged department like EnHM? Hon. Minister, Sir, I couldn't find any justification. Why do we have a separate Construction Wing to create infrastructure when the same work is being done by organizations like IRCON and other private entities?

Sir, I would take one minute more. People are worried. Your statement in the Lok Sabha tried to address a part of my worry. But, looking at the fate of Air India, my worry is - are we allowing the Indian Railways to go the Air India way? We don't have a National Carrier now. देखिए, अगर हम लोग...(समय की घंटी)... मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। आपने एक शहर को देखा है, उस शहर के साथ प्लेटफॉर्म का, रेलवे स्टेशन का एक रिश्ता है। मैं बाज़ार का विरोधी नहीं हूँ।

लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ार के समक्ष आत्मसमर्पण करने से हमारे पास कुछ खास नहीं बचेगा। मैं फिर स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी को इस अफसाने में लाकर कहना चाहता हूँ। उन्होंने 1990 में भी यह बात कही थी और कई दफा कही थी कि हमें इतनी सनद रहे कि इतिहास हमारा मूल्यांकन दो-चार फैसलों से नहीं करता है। वह फैसलों की लम्बी श्रृंखला को गौर से देखता है और वह यह देखता है कि क्या आपके निर्णय किसी के दबाव में थे या किन्हीं के दबाव में थे। दबावमुक्त निर्णय लेना आपको ऐतिहासिक बनाता है, वरना इतिहास गढ़ने की कोशिश तो कई सिकंदरों ने भी की थी, जय हिंद, सर!

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : उपसभापति महोदय, रेल बजट पर चर्चा हो रही है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस तरह बुलेट ट्रेन चल रही है, उसी तरह से हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

*"नरेन्द्र मोदी जी ने बंद किया है कांग्रेस और विपक्षी दलों का खेल,
क्योंकि अश्वनी वैष्णव और दानवे रावसाहेब दादाराव
चला रहे हैं सही दिशा से भारतीय रेल,*

आप कितना भी करो आपस में तालमेल,
लेकिन 2024 में मोदी जी ही करेंगे सबको फेल,
गलत काम करोगे, तो जाओगे जेल और
25 साल तक चलती रहेगी मोदी जी की रेल,
रेल गरीबों का रथ है, रेल गरीबों का पथ है, यह गरीबों का मत है,
यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ जंग,
लेकिन मोदी जी दे रहे हैं ट्रेन को बहुत ही सुंदर रंग।
इसलिए विपक्षी दलों का सपना हो रहा है भंग,
और कांग्रेस से सारे लोग हो गए हैं तंग।"

हम सभी लोग रेल को सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और रेल अभी फास्ट चल रही है। मुम्बई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलने वाली है। मेरी मांग है कि वाया मुम्बई से केरल के लिए भी एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। मुम्बई से दिल्ली के लिए भी एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। मुम्बई से नागपुर के लिए बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, चेन्नई के लिए भी बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, बेंगलुरु के लिए भी बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, हैदराबाद के लिए भी बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, लखनऊ के लिए भी बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, रायपुर के लिए भी बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। सभी जगहों पर बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। रेल के स्टेशनों में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। बहुत सारे स्टेशन्स सुंदर बनाए जा रहे हैं। वहां खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। रेल में काफी सुधार हो रहा है। कोरोना के कारण बेड नहीं मिलता था, लेकिन वह अब मिलना चाहिए, क्योंकि हमने रेल में प्रवास करना शुरू किया है। सभी लोगों की ऐसी मांग है। कोरोना जा रहा है और रेल में बेड आ रहा है। इसी तरह बेड भी आ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आपका 1 लाख, 40 हजार करोड़ का बजट है और रेल के लिए पैसे की कमी नहीं है। अभी फास्ट ट्रेन भी चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, विद्युतीकरण अच्छा हो रहा है, डबलिंग अच्छी हो रही है, मुम्बई में लोकल ट्रेन भी अच्छी चल रही है, लेकिन लोकल ट्रेन बढ़ाने की आवश्यकता है। मुम्बई में एक ट्रैक बढ़ाने की आवश्यकता है, तो लोकल ट्रेन के लिए भी दो ट्रैक्स बढ़ाने की आवश्यकता है। मुम्बई के आजू-बाजू में, रेलवे स्टेशन के बाजू में बहुत सारी जगह है, उस जगह पर मॉल बनाने की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशन के बाजू में जहां पर झोंपड़पट्टी है, स्लम है, वहां पर अच्छी बिल्डिंग बनाने की भी आवश्यकता है, उसके लिए राज्य सरकार से बात करके गरीब लोगों की मदद करने की आवश्यकता है, इसीलिए हम सब लोग आपके साथ हैं।

सर, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे मंत्री जी महाराष्ट्र से हैं, खाली मंत्री पद देने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पैसा मिलना चाहिए, मतलब महाराष्ट्र के लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और महाराष्ट्र को ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए हम जरूर आपको प्रस्ताव देंगे। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में नई-नई ट्रेनें शुरू होनी चाहिए। मुम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम देने के बारे में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वीटी स्टेशन है, एयरपोर्ट शिवाजी महाराज के नाम से है, यह बहुत अच्छी बात है और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सभी के मन में आदर है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का कार्य क्षेत्र मुम्बई रहा है, इसीलिए मुम्बई का जो सेंट्रल

स्टेशन है, उसको बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए। यह हमारी दरखास्त है। आप मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं कब अपना भाषण बंद करूं। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, रेल मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूं और भविष्य में रेलवे बहुत अच्छा काम करती रहेगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। मैं दो शब्द कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri H.D. Devegowda.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, I won't take much time. Hon. Kharge ji was the Railway Minister and some of those projects which were sanctioned in 1996 during his period were completed and inaugurated. These are Hassan-Bengaluru, Chikkalur-Bengaluru. Why I am telling this is that demand for the new lines or for completion of old lines, which you have sanctioned, are increasing because compared to other transport systems, the rail travel is very cheap. Sir, he knows more than me about the railway lines which I had sanctioned. Munirabad to Mehaboobnagar, which connects both Karnataka and Andhra Pradesh, is one of the best routes. They have covered half portion and the railway track has been completed and the trains are running. In each compartment 200 to 300 people are travelling today. If it is going to be completed, it will be one of the best railway projects, which I had approved in 1996.

Sir, let me talk about the hon. Railway Minister. It is not the question of praising him. He has an administrative skill. When I met him, he called the concerned officers, took the decisions on the spot, and, directed the officers who had met me. Though I do not go outside, somehow, I come to Rajya Sabha. The only thing is when I am coming here, I should see that something is done in some of these areas, where we are suffering in Karnataka. Sir, let me mention the new Railway lines, which have been demanded from the beginning. One is Shravanabelagola to Medikeri, a new line on plain area, and, there is no major problem to run that railway line except one bridge. Second one is from Mysore to Medikeri via Hunsur. These are going to provide more connectivity to the rural areas. Also, from Mangalore to Bengaluru, we can run the train.

I am now going to make some suggestions. Another thing which I had sanctioned is from Bengaluru to Kanakpura. This is a new railway line which I had sanctioned. The survey had also been completed. Only because of the scarcity of funds, it has been dragging on. So, I would like to request your goodself on this. Yes, about railway lines, it should go to the inner areas. But in south Karnataka, Kharge ji is there, except Mangaluru to Konkan Railway, there is only coastal area.

Connecting the areas from Mysore to Mangaluru and from Shravanabelagola to Madikeri will be more helpful. You can discuss with your officers and take decision at least for the survey. And, subsequently, you can take a decision about providing funds, if it is feasible. Whether it is feasible or not is going to be a big issue. I would like to tell only one word to your goodself about the Mysore-Arsikere railway line. Jaffer Sharief was the Railway Minister at that time. When I discussed this issue as a Member of the Lok Sabha, he said it is not feasible and we are going to cancel it. Some tracks were also removed. It was a metre gauge line. I took a decision after I took oath on the floor of the House. As the oath-taking process got over, the next day I called the Chairman, Railway Board. Shri Ram Vilas Paswan was the Minister. He is no more now. Today, 28 trains are running on that line. What the officers told was that it was not workable, not feasible. They removed some railway tracks also. I took a decision. It was not for me personally. It was for the public. Today, 28 trains are running there. What system we had adopted at that time was, priority should be given to the places where after the railway line is completed, the returns are high. Unless you complete a railway line, how are you going to get the industrial development or any other development? If there is no track, how can we expect the returns? Those days, we changed the system itself. First we drew the railway line and then thought of the returns. I don't want to go back to all those days. I am going to give the details of some of the pending projects. New line at Bengaluru-Chamarajanagar via Kanakpura section and Mysuru-Hunasuru-Piriyapattana-Madikeri-Mangaluru is pending. Construction of Belur-Hassan railway line instead of Belur-Sakaleshpur line in Chkkamagaluru-Belur-Sakleshpura, which I have already discussed, is also pending. Work on Munirabad-Mehaboobnagar is going on. It is half done. When the budget scarcity is removed, we may see that it is completed. Another project is Chickmagalur-Sakaleshpur new line linking up of Sakleshpura in lieu of Hassan-Belur-Chickmagalur-Sringeri. Sringeri is one of the important places all over India. So many tourists will come. I have been demanding this for the last 15 to 20 years. Modification in the proposed Shivamogga-Ranebennur rail route to Shivamogga-Yalavigi connection on the ongoing Gadag-Yalavigi project is also required.

Another project is Shravanabelagola-Holenarasipura-Arakalagudu-Somvarpet-Madikeri-Mangaluru. Out of these works, two-three are new works and others are ongoing works. Please see to it that they are completed. I am not going to take much time. I have given only a few suggestions. My experience, when I met him first time, is that as an administrator he has taken some decision. Today, on the floor of the House, I am making a humble request to him to see to it that these

proposals are considered. Sir, I want to express my sincere thanks for having given me this much time. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापति : माननीय सकलदीप राजभर जी।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे रेलवे के ऊपर चर्चा में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं रेलवे के कार्यकरण से संबंधित चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सान्निध्य में न केवल रेल सुविधाओं, वरन् अन्य सुविधाओं में भी दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जैसे सड़क, हाईवे व एक्सप्रेसवे परिवहन, हवाई यातायात एवं देश-विदेश में प्रख्याति, इत्यादि विकास की उड़ान देखने को मिल रही है। इसलिए आज मैं माननीय प्रधान मंत्री जी सहित माननीय रेल मंत्री जी को देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों के प्रयास से पूरे भारत की जनता की सुविधा के लिए रेल लाइनों का जाल बिछ रहा है, रेलवे लाइन का दोहरीकरण व विद्युतीकरण हो रहा है, सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा, चहुंमुखी विकास, स्वच्छता एवं शुद्ध जल, जनमानस को बैठने के लिए विश्रामालय, प्लेटफॉर्म पर कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है तथा स्टेशनों की साफ-सफाई को चकाचौंध कर दिया गया है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ऊपरगामी ब्रिज और लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है व समय की बचत के लिए तेज रफ्तार की गाड़ियाँ, जैसे राजधानी, तेजस, वंदे भारत आदि चलाई जा रही हैं। जनता के लिए गाड़ियों में सुरक्षा सहित मोटरसाइकिल स्टैंड, टैक्सी स्टैंड व ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन को पार करने के लिए अंडरग्राउंड समपार हर गाँव के सामने बनाए जा रहे हैं। ट्रेनों से जनता व पशुओं को बचाने के लिए रेल लाइनों के दोनों तरफ जाली और चहारदीवारी बनाई जा रही है। जनता को गाड़ी के कोच की जानकारी देने के लिए तथा रेल संबंधी जानकारी देने के लिए लाउडस्पीकर से प्रचार एवं पूछताछ केन्द्र स्थापित किया गया है। जब शाम होती है, तो दीपावली के दिन जैसे चारों तरफ स्टेशन जगमगाता रहता है। यहाँ तक कि बुजुर्गों एवं बीमार पीड़ितों के लिए लोअर बर्थ की टिकट के रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। रेलवे के उक्त सारे कार्य सराहनीय हैं। रेलवे एक ऐसा विभाग है, जो चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, सबको रोजी-रोटी और नौकरी देता है।

इसी कड़ी में मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मेरे गृह जनपद बलिया समेत जनपद मऊ नगरपालिका के दोहरीघाट से तहसील मधुबन, तहसील बेल्थरा रोड, तहसील सिकंदरपुर, ब्लॉक मनियर, तहसील बांसडीह टाउन एरिया - सहतवार, तहसील बैरिया होते हुए बकुल्हा घाट, सुरेमनपुर तक नई रेल लाइन की आवश्यकता है। भूतपूर्व रेल मंत्री, माननीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में भारत के पूर्वोत्तर व पश्चिमोत्तर को जोड़ने के लिए सर्वे भी हुआ था। मैंने भी 17.3.2021 को उक्त नई रेल लाइन हेतु व गोरखपुर से भटनी-बनारस से नई दिल्ली तक के लिए एक ट्रेन के लिए तथा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पश्चिमी एकमात्र बेल्थरा रोड स्टेशन से जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके ठहराव के लिए राज्य सभा में यह विषय उठाया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी मिला था और इन्होंने सर्वे कराने का आश्वासन भी दिया था। हमें विश्वास है कि हम

जैसे छोटे लोगों की बात वे अवश्य सुनेंगे, हम अपने यहां की जनता की तरफ से इसके लिए हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे द्वारा उठाई गई उक्त मांगों को जनहित के चहुंमुखी विकास और सुविधा के लिए बजट में शामिल करने और स्वीकृत करने का कष्ट करें, जय हिन्द, जय भारत!

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, सबसे पहले मैं माननीय उपसभापति जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मैंने चार रेल मंत्री देखे हैं। पहले मैंने बाबू जगजीवन राम जी को देखा, उनके बाद माननीय नीतीश कुमार जी को देखा, फिर माननीय लालू जी को देखा और उनके बाद माननीय रामविलास पासवान जी को देखा। इन सबकी अपनी अलग-अलग कार्यशैली थी, लेकिन ये चारों लोग बिहार से ही थे। इन लोगों ने रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन किए और भारतीय रेलवे को देश में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलवाया, जिसकी चर्चा आज भी पूरे विश्व में होती है। जैसा प्रो. मनोज झा जी ने अभी बताया, इनमें से माननीय लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य अभी खराब है।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे यह चाहूंगा कि सदन के नेता के रूप में आप इसमें जो सुधार कर सकें, जो मदद कर सकें, अवश्य करें। मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहूंगा कि आपसे पहले जो रेल मंत्री रहे हैं, उनकी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपसे पहले, तीन अन्य रेल मंत्रियों से भी मैं अपनी बातें कह चुका हूं, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि हमने जो सुझाव दिए थे, उन चीजों में अभी तक न तो कोई परिवर्तन हुआ, न उन पर कोई चर्चा हुई और न ही उनका पालन हुआ। आज मैं पुनः उन बातों को दोहराना चाहता हूं।

माननीय रेल मंत्री जी, आपका उपक्रम एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है, लेकिन इस उपक्रम में आज मैं यह देख रहा हूं कि इसका लगातार निजीकरण होता चला जा रहा है। इसमें आपने कुछ ट्रेन्स ऐसी ला दी हैं, जिनको निजी हाथों में दे दिया गया है। जब हम लोग सांसद बनते हैं, तो हम लोगों को एक पास मिलता है, जिस पर लिखा होता है - 'Any Train, Any Class', यानी आप किसी भी ट्रेन और किसी भी क्लास में यात्रा कर सकते हैं। महोदय, लेकिन एक ट्रेन ऐसी चल रही है, जो कानपुर से निकलती है, जिसका नाम है 'तेजस एक्सप्रेस'। हमने सोचा कि हम भी इस ट्रेन पर बैठ कर देखें और हमने 'तेजस एक्सप्रेस' में जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सांसदों को इस ट्रेन में फ्री सफर करना एलाउड नहीं है, आपको इसकी टिकट लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें जा सकेंगे। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो कार्ड मिला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है - 'Any Train, Any Class'। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि या तो वे हम लोगों को ऐसी ट्रेन्स में यात्रा करना एलाउ करवाएं अथवा उस कार्ड में से 'Any Train, Any Class', इन शब्दों को हटवा दिया जाए। 'Any Train, Any Class' की जगह उस कार्ड पर यह लिख दिया जाए कि अमुक-अमुक ट्रेनों में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। महोदय, सांसद की हैसियत से हमें जो सम्मान मिला हुआ है, उसमें इस चीज से कहीं न कहीं कमी आती है। जब लोग इसको देखते हैं, तो इसकी चर्चा होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसमें परिवर्तन जरूर करवा दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, जहां तक ट्रेन में सुविधाओं का प्रश्न है, यह बात सही है कि सफाई की व्यवस्था अब पहले से अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जितनी दुर्घटनाएं पहले हो रही थीं, दुर्घटनाओं की संख्या में भी अब कमी आई है, यह भी अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

महोदय, आजकल एक दुर्घटना बहुत अधिक हो रही है, जो छुट्टल सांड होते हैं, वे ज्यादातर ट्रेनों के सामने आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी मौतें हो जाती हैं। बहुत सारी फास्ट ट्रेन्स ऐसी हैं, जिनको इन सांडों के कारण जहां-तहां रुकना पड़ता है। विदेशों में मैंने देखा है, वहां पर जो ट्रेन्स के ट्रैक्स होते हैं, वे सब तरफ से घिरे रहते हैं, जिससे ट्रेनों के सामने कोई जानवर नहीं जा सकता है। हालांकि यह बहुत बड़ा काम है, शायद हमारे यहां ऐसा संभव न भी हो, लेकिन आप कोई ऐसी व्यवस्था करवाइए, ताकि यह जो दिक्कत आती है, यह खत्म हो सके।

महोदय, मैंने पहले भी कई बार एक बात कही थी कि जो ज्यादा दूरी की ट्रेन्स हैं, राजधानी इत्यादि जो सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, इन ट्रेन्स में कभी-कभी मैं एनाउंसमेंट्स सुनता रहता हूं कि यदि कोई डॉक्टर साहब इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हों, तो कृपया फलां-फलां कोच में आ जाएं, यहां एक यात्री बीमार हो गया है। मैं देखता हूं कि अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैंने स्वयं देखा है, हमारे कानपुर के एक साथी थे, जिनका राजधानी ट्रेन में देहांत हो गया था, क्योंकि इन ट्रेन्स में डॉक्टर्स की सुविधा नहीं मिल पाती है। कुछ दिन के लिए इन ट्रेनों में डॉक्टर्स की व्यवस्था रखी गई थी, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया गया। मैं जानता हूं कि इसके लिए आपको बहुत अधिक कीमत अदा करने पर डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन कम से कम यात्रियों को फर्स्ट एड सुविधा देने के लिए, आजकल GNM या ANM पास किए हुए जो लोग मिल जाते हैं, उनमें से किसी को लगवा दें। जो फास्ट गाड़ियां चलती हैं, कम से कम उनमें ऐसी व्यवस्था अवश्य हो जाए, ताकि किसी भी यात्री के अचानक बीमार होने पर उसको फर्स्ट एड की सुविधा मिल जाए और उसकी जान बचाई जा सके, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि लालू जी ने 'गरीब रथ' ट्रेन्स चलाई थीं, उनमें सबसे कम खर्च में गरीबों ने इन गाड़ियों का मज़ा लिया। यह लालू जी की देन थी। जो लोग कभी भी ऐसी गाड़ी में नहीं चले थे, वे लोग ऐसी में मौज से सफर करते हैं, भले ही उनके घर में ऐसी न हो। वे लोग वापिस आकर तारीफ करते हैं कि हम लोग गरीब रथ में घूमकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप गाड़ियों में और सुविधाएं दें, ताकि गरीब लोग भी इनका आनन्द ले सकें।

महोदय, सारी राजधानी ट्रेन्स कानपुर स्टेशन से जाती हैं। सवेरे चार-पांच राजधानी ट्रेन्स कानपुर से निकलती हैं। उनमें एक डिब्रूगढ़ राजधानी चलती है। मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि इसका समय चेंज कर दिया जाए, क्योंकि डिब्रूगढ़ राजधानी पहले यहां से करीब तीन बजे चलती थी, तो यहां से जाने वाला आदमी समय से घर पहुंच जाता था, अब आपने इसे सुबह साढ़े चार बजे कर दिया। हम चाहेंगे कि डिब्रूगढ़ राजधानी का समय एक बार फिर से चेंज किया जाए। क्योंकि हमारे पिताजी जब सांसद थे तो वे अक्सर इसी गाड़ी से जाया करते थे और हम भी उसी गाड़ी से जाते हैं, लेकिन इसका समय ऐसा है कि पहुंचने पर रात हो जाती है। इसके लिए हमने कई बार कहा है कि यदि आप इस पर विचार कर सकें, तो अच्छा होगा।

इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि माती कानपुर देहात का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय माननीय मुलायम सिंह यादव की देन थी। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा

हूँ कि कानपुर देहात को मुख्यालय बने लगभग तीस साल हो गये, लेकिन कानपुर मुख्यालय का अपना रेलवे स्टेशन आज तक नहीं बना। वहाँ तीन रेलवे स्टेशंस पड़ते हैं - लालपुर, पुखरायां और रूरा। इन तीनों रेलवे स्टेशनों में से किसी एक को आप अच्छा कर दें, आप सिर्फ इतना ही कर दें कि देहात मुख्यालय का यह स्टेशन होगा, ताकि जो सुविधाएं शहरों में मिलती हैं, वे सुविधाएं वहाँ मिलें और आम लोगों को उनका लाभ मिल सके।

इसके अलावा बार-बार यह चर्चा हो रही है कि बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन बुलेट ट्रेन का चलना अभी मुश्किल काम है, अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि बुलेट ट्रेन यहाँ से चलेगी। क्योंकि जब तक आप ट्रैक की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे, ट्रैक को आप कवर नहीं करेंगे, तो फास्ट ट्रेनों का चलना संभव नहीं लगता है। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि जो छुट्टे जानवर घूमते हैं, चाहे वह गाय हो, सांड हो अन्य कोई जानवर हो, पहले आप इनसे अपने ट्रैक्स को बचाने का काम करें। मैंने विदेशों में देखा है कि कोई भी जानवर ट्रैक पर या रोड पर नहीं मिलेगा। यहाँ स्थिति यह है कि जानवर हर जगह दिखाई पड़ते हैं। यदि आप इसकी व्यवस्था करेंगे, तभी आप बुलेट ट्रेन चला पाएंगे, वरना बुलेट ट्रेन का चल पाना संभव नहीं है।

अंत में इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहूँगा कि यह सांसदों के मान-सम्मान का प्रश्न है, इसलिए ऐसी गाड़ियों में, जहाँ सांसदों को यात्रा करने से रोक दिया जाए कि आप इस गाड़ी में नहीं जा सकते हैं, आप इसकी ठीक से व्यवस्था करें, वरना उनमें आई.कार्ड पर लिखवा दें कि इन-इन गाड़ियों में सांसदों का चलना वर्जित है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। रेल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और हमारे देश में रेल में सफर करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसी बात पर विचार करते हुए रेलवे पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। भारतीय रेलवे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेल देश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का काम करती है और लोगों को छोड़ने का काम भी करती है। सभी लोग जानते हैं और अभी अठावले जी ने भी कहा कि यह गरीबों का रथ है। वास्तव में रेल गरीबों का रथ है और हमारे देश में रेल से चलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए सभी रेलवे स्टेशनों तथा रेलों में सब सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब बातों पर हमारी सरकार लगातार ध्यान देने का काम कर रही है।

मैं बचपन से देख रही हूँ कि मेरी माँ भी कहीं आया-जाया करती थीं, तो वे ज्यादातर रेल से ही आया-जाया करती थीं। वे कहती थीं कि मुझे रेल से जाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि 2014 से पहले स्टेशनों और ट्रेनों की क्या हालत थी, यह सभी जानते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि जब भी बजट आता है, तो वह बढ़ कर ही आता है और देश की जनता को सुविधा भी प्रदान करता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय रेलवे लगभग 70 हजार किलोमीटर से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके साथ ही रेलवे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक है। हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए मालगाड़ियों की भी

जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान और बहुत सारे उद्योग भी ऐसे हैं, जो अपने माल को रेल के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने रेलवे में निवेश के कार्य को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया है, ताकि मौजूदा सुविधाओं को बरकरार रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रख कर केन्द्र सरकार ने बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। यह बहुत बड़ी राशि है। नई लाइन निर्माण तथा लाइनों के दोहरीकरण में भी बढ़ोतरी की गई है। इसमें पहले की तुलना में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इसमें 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जहाँ 1,520 किलोमीटर प्रति वर्ष नई रेलवे लाइन, डबल लाइन का निर्माण हुआ था, वहीं वर्ष 2014 से 2021 में यह बढ़ कर 2,533 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। महोदय, सिक्किम को छोड़ कर सभी सात पूर्वोत्तर राज्य रेल लाइन से जुड़ चुके हैं और सिक्किम राज्य को भी रेल लाइन के नेटवर्क से जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है।

महोदय, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए और रेल ढुलाई की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से पूर्व से पश्चिम तक 1,110 किलोमीटर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इससे भी देश के लोगों को सुविधा होगी और यह कदम स्वागत योग्य है।

महोदय, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी जरूरतों को ध्यान में रख कर रेलवे ने 901 ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा के माध्यम से 2,087 टैंकर्स और 36,840 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश के सभी राज्यों में पहुँचाने का काम किया है। जब सेकंड वेव आई, तब फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपना कार्य नहीं रोका और सभी राज्यों में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया। आप सभी लोगों ने देखा कि श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई गईं। दिल्ली में भी जो बड़ी संख्या में मजदूर, श्रमिक तथा अन्य लोग रहते थे, उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया था, लेकिन रेलवे ने उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाने का काम किया, ताकि वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच सकें। महोदय, मैं मेरठ से आती हूँ और मैंने वहाँ भी देखा कि स्पेशल ट्रेन्स चला कर वहाँ रह रहे लोगों को कोलकाता, मुम्बई, बिहार आदि संबंधित जगहों पर भिजवाने का काम किया गया, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह बहुत बड़ा कदम था और यह बहुत जरूरी भी था - हमारे श्रमिक भटक रहे थे, उनको उनके घर तक पहुँचाने का काम किया गया।

प्रधान मंत्री जी ने कोविड को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आपदा को अवसर में बदला, रेल मंत्री जी ने सप्लाई चेन को चालू रखा और वे इसे आगे बढ़ाते रहे।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के विषय में भी जरूर कहूँगी। हमारे उत्तर प्रदेश का जो बजट है, वह वास्तव में बहुत सराहनीय है। **...(समय की घंटी)...** 2022-23 का बजट, उत्तर-पश्चिम रेलवे के लिए बजट, यह 6,724 करोड़ रुपये का है। यह पहले से 43.51 प्रतिशत ज्यादा है।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र मेरठ के लिए एक माँग करना चाहती हूँ। यह माँग बहुत दिनों से चली आ रही है। हस्तिनापुर एक जगह है, वहाँ पर जैन लोगों का बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। वहाँ पूरे देश से जैनी जाते हैं। इसके साथ ही, कौरव-पांडवों का भी एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है। **...(समय की घंटी)...** मैं कहना चाहती हूँ कि मेरठ से हस्तिनापुर को जोड़ा जाए और वहाँ एक स्टेशन भी बनाया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आपने मुझे रेल बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, इस समय भारत की रेल चमक रही है। इस संबंध में मैं अभी और चर्चा करूँगा, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि एक माननीय सदस्य ने रेल मंत्री के संबंध में जो धारणा व्यक्त की थी, वे आईएस रहे हैं, जिलाधिकारी रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इनके चेहरे को नहीं देखा, इनके दिल को नहीं देखा। अगर इनके चेहरे को देखा होता, तो शायद उसमें वे मोह गए होते और दिल को देखा होता, तो वे रेल में चलने वाले सफर को भूल गए होते।

श्रीमन्, जब माननीया वित्त मंत्री जी ने रेल मंत्रालय के बजट को रखा था, तब उन्होंने रेल के लिए 1,40,367 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित किया था। पहले रेल का अलग बजट हुआ करता था, लेकिन पूरे वित्त वर्ष के बजट में ही रेल बजट को भी सम्मिलित किया गया। यह इस नाते किया गया, क्योंकि दो-दो फंक्शंस हो जाया करते थे और लोगों ने दो-दो फंक्शन रखने का काम इस नाते किया कि उन दो-दो फंक्शंस का आनंद उठाया जाए। अतः काम कम और आनंद अधिक! हमारी सरकार ने काम को प्राथमिकता देते हुए एक बात कही - 'सबका साथ, सबका विकास,' इसलिए सबको साथ लेते हुए रेलवे के विकास की गति को तेज कर दिया। श्रीमन्, अगर रेलवे को देखा जाए कि रेलवे में इस समय क्या है, तो 2021 का वर्ष ऐसा रहा, जिसे भारतीय रेल के लिए परिवर्तन के वर्ष के रूप में माना जाएगा। इसके बुनियादी ढांचे में विकास हुआ, नवाचार में नेटवर्क की क्षमता का विस्तार हुआ, माल ढुलाई इत्यादि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, रेल ने माल ढुलाई संचालन से राष्ट्रीय आर्थिक सुधार में योगदान दिया और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि यह पूरा विश्व कोविड में जूझ रहा था, भारत भी लॉकडाउन में जूझ रहा था, सब कुछ बंद था, लेकिन अगर कुछ बंद नहीं था, तो रेलवे की पटरियों पर रेल का चलना बंद नहीं था।

उस समय लोग एक स्थान पर रह रहे थे और सोच रहे थे कि वे क्या खाएँगे, तो चलती हुई रेल की पटरियों ने यह आवाज़ दी कि आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, माल की ढुलाई करके आप लोगों तक हम सामान पहुँचाने का काम करेंगे और यह काम बखूबी किया गया। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेल विभाग ने रेल को पूरे तौर पर इस काम में लगा दिया। मैंने रेलवे में यात्री रेल तो नहीं, लेकिन माल ढोने वाली गाड़ियों का विराम कभी भी नहीं देखा था। वे चलती रही थीं और लोगों तक सब कुछ पहुँच रहा था। लॉकडाउन में किसान यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि हमने जो खेती की है, उस खेती का क्या होगा, वह बाज़ारों तक कैसे जाएगी? मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार 'किसान रेल' चलाकर बेंगलुरु के सामान को दिल्ली में लाकर उससे यहाँ के बाज़ारों को पाटने का काम किया, वहाँ के किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया। यह रेल का एक नया और अद्भुत स्वरूप था। जब लॉकडाउन में लोग जूझ रहे थे, तब भी रेल चलती रही, उसकी गति कभी नहीं थमी। इस प्रकार यह किसानों के लिए भी वरदान साबित हुई।

मान्यवर, आपने भी देखा होगा कि उस समय जब लोग कमेंट कर रहे थे, कोविड का नाम सुनते ही अस्पतालों में जाने से डर रहे थे, तब देश के प्रधान मंत्री नये-नये निर्णय ले रहे थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना नहीं मरना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा रैक लगवा दिया और लिक्विड ऑक्सीजन को एक स्थान से लाकर दूसरे

स्थान तक पहुँचाकर लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। इसका श्रेय भी पूरे तौर पर रेलवे को है। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी और रेलवे के अधिकारियों को साधुवाद देना चाहूँगा। चाहे वे अधिकारी छोटे हों या बड़े हों, उन्होंने अपने अधिकार को अधिकार नहीं माना, बल्कि उसे वे अपना कर्तव्य मानकर कार्य करते रहे। इस प्रकार से रेलवे ने कार्य करके दिखाया।

श्रीमन्, हमने विकास भी किया। जब माननीय एलओपी साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने समय की कुछ बातें याद दिलाईं। हम लोगों को भी उन बातों का स्वागत करना चाहिए, जिनकी याद उन्होंने दिलाई। रेलवे की जिन परियोजनाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कुछ किया है, उसके लिए मैं केवल एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अपने भाषण में कुछ शब्द जोड़ दिए होते कि जो काम हमने अधूरा छोड़ दिया है, उसको भी आपने ही पूरा किया है, किसी और ने पूरा नहीं किया, तो ज्यादा अच्छा होता। अगर उन्होंने ये शब्द जोड़ दिए होते कि आप अपने कार्य को तो पूरा कर ही रहे हैं, मेरे अधूरे कार्य को भी पूरा कर रहे हैं, तो शासन की परम्परा के अनुरूप वे बातें पूरी हो गई होतीं। मैं कहना चाहता हूँ कि रेलवे की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 1,37,000 करोड़ रुपये खर्च करके हम रेलवे की अटकी हुई परियोजनाएँ पूरी करेंगे। वे कौन सी परियोजनाएँ थीं? वे कब की थीं? अगर वे उस समय पूरी हो गई होतीं, तो आज उनको पूरा करने की जरूरत नहीं थी और कुछ कह ही नहीं पाते, लेकिन आपकी छोड़ी हुई परियोजनाओं को भी पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है, तो इसके लिए साधुवाद के पात्र रेल मंत्री हैं, भारत के प्रधान मंत्री हैं, भारत की सरकार है। इस बात को पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं, बल्कि विकास के नाते आप सभी लोगों को भी कहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहेंगे। ये इस नाते नहीं कहेंगे कि विषय समालोचना का नहीं, आलोचना का है। अगर ये समालोचना करेंगे, तो फिर इनको सब बातें कहनी पड़ेंगी।

5.00 PM

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 901 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई थीं और 36,840 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाकर लोगों के जीवन को बचाने का काम किया था। यह भारत सरकार की कार्यनीति है, जिस नीति को आप लोगों ने कभी अपनाने का प्रयास नहीं किया।

मान्यवर, इतना ही नहीं, 4,621 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं। माननीय संजय सिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं, वे बहुत चर्चा करके गए हैं, लेकिन वे दिल्ली में मजदूरों तक की चिंता करने की स्थिति में नहीं थे। भारतीय रेलवे ने 4,621 श्रमिक ट्रेनें चलाकर 6.3 मिलियन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह काम यदि किसी ने किया है तो इस रेल विभाग ने किया है और भारत सरकार ने किया है। केवल आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि समालोचना होनी चाहिए।

महोदय, मैं यदि कोविड की एक-एक बात कहूँ तो बहुत समय हो जाएगा। महोदय, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए Vistadome कार्यक्रम लागू किया और उस कार्यक्रम के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो लोग हवाई जहाज से सफर करके जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अब वे रेलवे के उन दृश्यों को देखने के लिए हवाई जहाज को छोड़कर रेलवे के कोच में जाकर

बाहर के अद्भुत दृश्य को देखते हुए चलते हैं, यह सच है। लोग जो कहते हैं कि उसमें शीशा होता है, वैसे ही रेल मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का जो बजट होता है, वह शीशे की तरह होता है, पूरे तौर पर दिखता है, लेकिन जिसको नहीं दिखता हैं - जैसे रेल का जो एसी कोच होता है, उसके अंदर दुनिया भर की बातें होती हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जब वे बाहर से देखते हैं, और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वे केवल आलोचना करते हैं। जब उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अंदर नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि वे आलोचना कर चुके हैं। ...**(व्यवधान)**... मैंने देखा है, तभी मैं कह रहा हूं।

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप लोग आपस में बात न करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल : मान्यवर, रेलवे ने नई लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण आदि पर काम किया है, इसमें 66 परसेंट से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में जहां यह 1,520 किलोमीटर था, माननीय रेल मंत्री जी ने वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के बीच में उसे बढ़ा कर 2,533 किलोमीटर करने का काम किया है। 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रेलवे ने अद्भुत कार्य किया है, रेलवे ने उसमें अत्यधिक वृद्धि करने का काम किया है।

श्रीमन्, यहां चर्चा चल रही थी कि बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है, उसे बनाने की क्या ज़रूरत है! लेकिन अगर भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है तो जैसे four lane और six lane की सड़कें बनीं, उससे लोगों का डीज़ल-पेट्रोल बचा और समय भी बचा, इसलिए कि जब four lane और six lane की सड़क बन गई और जब वे उस चमचमाती हुई सड़क पर चलते हैं तो बहुत जल्दी घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारा काफी समय बच गया है। वही काम बुलेट ट्रेन का भी है। जब बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक जाएगी तो वह सफर सिर्फ ढाई-तीन घंटे का हो जाएगा, उससे कितनी बचत होगी, इस पर विचार नहीं करते हैं, विचार यह करते हैं कि लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, इससे गरीबी कहां तक कम होगी।

दिल्ली शहर में मकान तक न देने वाले लोग संसद में आकर इस बात की आलोचना करते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि पहले झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए मकान दें, उसके बाद बुलेट ट्रेन पर चर्चा करें। ...**(समय की घंटी)**...

मान्यवर, मुझे मालूम है कि माननीय रेल मंत्री जी अपना बयान देंगे। अभी तक मैं इनके लिए बोल रहा था, अब कुछ अपने लिए भी बोल लूं। मैं गोरखपुर से आता हूं। सहजनवां से दोहरीघाट तक एक लाइन है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि वह स्वीकृत हो चुकी है और शायद इसके लिए बजट का ऐलोकेशन भी हुआ है या नहीं हुआ है, वे इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। अगर वे बजट का ऐलोकेशन कर देंगे, तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा और गोरखपुर से वाराणसी की दूरी बहुत कम हो जाएगी। दिल्ली में हम लोग एक escalator से कई प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, लेकिन मेरा एक और आग्रह होगा कि गोरखपुर में एक ही है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर का है। पहले मुगलसराय था, अब गोरखपुर का हो गया है। वहां भी चढ़ने और उतरने की सुविधा दे दी जाए और कर्मचारियों को यह कह दिया जाए कि सरकार को बदनाम न करें और जब ट्रेन्स आती हैं, तो उसको बंद न रखें, उसको खुला रखें, ताकि लोग सुविधापूर्वक उतर जाएं, वह बेहतर होगा।

उपसभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि रेल हमारी लाइफलाइन है। पक्ष और विपक्ष को हमारी लाइफलाइन को बढ़ाने के लिए सहयोग देना चाहिए। अगर सरकार कोई ऐसी बात करती है, जिसमें उनको यह लगता है कि सुधार होना चाहिए, तो सुधार की बात करनी चाहिए। यहां पर रेल को छोड़कर आप आई.ए.एस. रहे हैं, आई.पी.एस. रहे हैं, उसके बारे में ही चर्चा हुई।...**(समय की घंटी)**... जो सरकार शिक्षा से लेकर रेल तक में भारतीय संस्कृति को पूरी तौर पर विकसित करने का काम कर रही है, उस सरकार के लिए कहा जा रहा है कि यहां के मुख्य मंत्री को लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है। हमने अयोध्या बना दिया, काशी भी बना दिया।...**(समय की घंटी)**... अगर देखना है, तो जाइए, इसी रेल में बैठकर काशी और अयोध्या को देखिए। ...**(व्यवधान)**... रेल मंत्री से कहेंगे, तो मैं उनको मुफ्त में भिजवाने का भी काम कर दूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय रेल मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि आपका जो कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से अद्भुत भारत के लिए चल रहा है, भारत के विकास के लिए चल रहा है और इसको आगे बढ़ाते रहिए। जैसे कोविड के समय में रेल की पटरिया चलती रहीं, वैसे ही पूरे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लोगों को पहुंचाने में, माल देने में, सुविधा देने में बढ़ाते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I would like to mention one thing in one minute. Sir, the hon. Railway Minister is here and he knows the road which connects India with Bhutan passes through Rangiya town, which is a junction also. A flyover was sanctioned, and, I think a survey has also been done, but the work has not yet been started. Over and above, I did not find mention of that in his reply. Would he throw some light on that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, discussion on the working of the Ministry of Railways is over. Now the hon. Railway Minister will reply.

रेल मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आरंभ में आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी शांति के साथ सभी ने अपने लॉजिकल प्वाइंट्स अच्छी तरह से रखे हैं और बहुत अच्छे वातावरण में डिबेट हुई। इसके लिए आपको और चेयर को धन्यवाद।

श्री उपसभापति : सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और कई अच्छी-अच्छी नोंक-झोंक भी हुई। डिस्कशन में ऐसा ही वातावरण रहे, तो डेमोक्रेसी की वैल्यू बढ़ती है और इन सभी इन्स्टिट्यूशन्स में लोगों

का विश्वास बढ़ता है। आप सभी ने जो सुझाव दिए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक disciplined सिपाही हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने जो आज सुझाव दिए हैं, माननीय सांसदों ने जिस तरह के प्वाइंट्स रोज किए हैं, कई तर्क सामने आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद और ये सभी बातें उस जिम्मेदारी को निभाने में जरूर मेरे काम आएंगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब मुझे यह जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने अपना विज़न शेयर किया। आप सभी जानते ही हैं कि प्रधान मंत्री जी रेल से बचपन से जुड़े हैं। वे एक अभाव वाली जिंदगी देख चुके हैं कि इस तरह की जिंदगी क्या होती है, रेल के प्लेटफॉर्म की जिंदगी क्या होती है, पटरियां क्या होती हैं, वहां ट्रेन्स आती हैं, वहां किस तरह का माहौल होता है, स्टेशन क्या होता है - वे इन सभी चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने अपना पूरा विज़न समझाया और विज़न के multi-dimensional aspects को अगर आप जानेंगे, तो आप भी जानेंगे कि वाकई में रेल के भविष्य को किस दिशा में जाना है और वह एक बहुत अच्छा भविष्य है। प्रधान मंत्री जी ने हमें एक सबसे बड़ा विज़न दिया - क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है - हम एक आम नागरिक की जिंदगी में रेलवे के जरिए क्या परिवर्तन ला सकते हैं, यह सबसे पहले सोचो! हमें किस तरह से जो रेलवे का एक एक्सपीरिएंस है, चाहे स्टेशन्स हों, ट्रेन्स हों, सेफ्टी हो या हमारे अफसरों का व्यवहार हो, इनमें परिवर्तन कैसे हो, उस पर फोकस करना है। दूसरा है - आत्मनिर्भर भारत। रेलवे सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको चलाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की जरूरत है, उसमें हम लोग कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तीसरा, एक बहुत बड़ा संकल्प लिया कि राष्ट्रनिर्माण के इस यज्ञ में, जो यह अमृत काल है, इस अमृत काल में Railways should become an engine of transformation for the entire economy. इस तरह से इस विज़न को लिया और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यथासंभव क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या प्रयास करने हैं, हम इन सभी में पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं।

उपसभापति जी, मानव्यर एलओपी साहब स्वयं रेल मंत्री थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनके समय में कई ऐसे decisions हुए, जो अगर जल्दी होते, तो उनका भी फायदा होता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं। उन्होंने कहा कि 2014 से ही शायद आपकी जिंदगी शुरू होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप यह कह रहे हैं, क्योंकि आपने इस मंत्रालय को संभाला है और आपका तो स्वयं एक बहुत लम्बा political career रहा है। आपने यह भी कहा कि काम कुछ नहीं हुआ, केवल प्रचार ही हुआ है। यह भी कहा कि कभी मुर्गी की बातें हुईं, कभी मसाले की बातें हुईं। मुझे पता नहीं कि मुर्गी, मसाले में क्या interest है, लेकिन मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहूंगा। रिकॉर्ड पर चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि यहां का जो वक्तव्य होता है, यहां पर जो भी बातें होती हैं, उनको आगे आने वाली जेनरेशन्स स्टडी करती हैं और देखती हैं कि क्या बातें हुई हैं।

मान्यवर, मैं आपके सामने केवल कुछ आंकड़े रखूंगा। हमारे सांसद श्री देरेक ओब्राइन साहब ने भी कहा कि हमारे पास विज़न था, हमने विज़न दिया, विज़न डॉक्यूमेंट बनाया। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था। बस! Full Stop. Vision! Full

Stop. उसके आगे क्या? Action - कुछ नहीं। केवल विज़न की बात करना और सामने केवल dramatic तरीके से रख देना, लेकिन action कुछ नहीं लेना।

उपसभापति जी, मैं आपके सामने actual facts रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि रेलवे में सबसे बड़ी problem capital investment की थी और यह सबसे बड़ी समस्या थी। पिछले 60-70 वर्षों में जितना रेलवे को capital चाहिए था, उतना capital कभी रेलवे में लगाया ही नहीं गया और इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़े कारण का, सबसे पहले कैसे प्रधान मंत्री जी ने समाधान किया, उस पर भी मैं आऊंगा।

उपसभापति जी, capital investment 2009 से 2014 के बीच में मात्र 45,980 करोड़ रुपये होता था। रेलवे जैसे संस्थान में, जिस तरह का, जिस साइज़ का हमारा नेटवर्क है, जितने हमारे यहां पैसेंजर्स जाते हैं, जितनी हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वह कुछ भी नहीं था। प्रधान मंत्री जी ने आते ही सबसे पहले इसको डबल किया, 2009 से 2014 के दौरान जो करीब 45,980 करोड़ रुपये था, 2014 से 2019 में उसको डबल करके 99,511 करोड़ रुपये किया। हम वहीं पर रुके नहीं, उसको आगे बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे और इस साल बजट में 2,45,800 करोड़ रुपये का capital investment का एलोकेशन किया गया। उनका आशीर्वाद हमें मिल गया, अब हमारी काम करने की क्षमता कितनी है, वह हम पर निर्भर करेगा। इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही राज्यों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। This is the Council of States. मेरा सभी सांसदगण से निवेदन है कि सभी राज्यों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" और उसके साथ 'सबका प्रयास' भी लगेगा। आप सबका प्रयास भी लगेगा, आप सभी साथ दें, सहयोग दें। आप दो कदम चलेंगे, तो हम पांच कदम चलने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई discrimination की बात नहीं है। There is absolutely no question of discrimination against any region or State. Let us work together. Let us make sure that we complete, realize and act on the vision given by the hon. Prime Minister.

उपसभापति महोदय, बहुत सारे विषय हैं, जो मेरे कई सांसद साथियों ने इधर से, उधर से, सब तरफ से कहे हैं। आप चाहे कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, उस पर जो काम हुआ है, केवल विज़न नहीं, काम हुआ है, उस काम को अगर आप देखेंगे, तो आपके सामने डेटा है, आपके सामने फैक्ट्स हैं। न्यू ट्रेक्स, जिसमें कि न्यू लाइन, गेज कंवर्जन, डबलिंग, ट्रिपलिंग और मल्टी ट्रेकिंग है। अगर 2009 से 2014 में हम उसे देखते हैं, तो वह मात्र 1,520 किलोमीटर पर ईयर था। 2014 से 2021 में डबल होकर वह almost 2,531 किलोमीटर पर ईयर हो गया और हमने इस साल का टारगेट इससे भी ज्यादा लिया हुआ है। हम इस वर्ष इसे तीन हजार से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटिजिक डिसेज़न था, क्योंकि 2014 में जब इस सरकार ने कार्यभार सम्भाला, तब प्रधान मंत्री जी ने सारा रिव्यू किया। बाकी देश में जिस तरह से एक पॉलिसी पैरालिसिस वाली सिचुएशन थी, वह रेलवे में भी थी। किस दिशा में जाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में जाना है, डीज़ल की दिशा में जाना है, मल्टी गेजिंग है - सारे मल्टी गेज को एक मिशन मोड में यूनीगेज कर देना है, किस तरह से आगे जाना है, उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था। आपने चाहे विज़न डायलॉग बनाया, लेकिन उसमें ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं थी। मैंने रेलवे मिनिस्टर्स के कई पुराने भाषण भी सुने हैं, यह ट्रेन चलानी है, वहां पर प्लेटफार्म का

यह काम करना है, इसके अलावा कहीं पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आने के तुरंत बाद यह बड़ा फैसला लिया कि हमें डीज़ल से हटना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पर जाना है और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच में जहां मात्र 608 किलोमीटर पर ईयर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, वह 2014 से 2021 के बीच में 3,440 किलोमीटर पर ईयर हुआ है और already हम लोग 50,000 किलोमीटर के आस-पास इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य कर चुके हैं और बाकी कार्य को शीघ्र कम्पलीट करना है।

उपसभापति महोदय, आज हम लोग एक और evolution कर रहे हैं कि आगामी 30 वर्षों के हिसाब से, 40 वर्षों के हिसाब से अगर सोचें, तो क्या हमें 2x25 KV पर जाना चाहिए? अभी हम 25 KV की इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है, उस पर काम कर रहे हैं। 1960 में जिस टेक्नोलॉजी का एपूवल हुआ था, क्या उससे नेक्स्ट जेनरेशन की टेक्नोलॉजी पर हमें जाना चाहिए, हम उस पर भी बहुत जल्दी डिजीज़न लेकर 2x25 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आगामी वर्षों में जब रेलवे को ज्यादा पावर की, ज्यादा ट्रैक्शन पावर की जरूरत पड़ेगी, तब यह फैसला नहीं लिया जा सकता।

आज से 10 साल आगे की सोच कर हमें आज ही फैसला लेना पड़ेगा, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे।

नॉर्थ-ईस्ट के बारे में कई मित्रों ने कहा और विशेष कर डा. मनमोहन सिंह जी, hon. former Prime Minister साहब के बारे में कहा कि वे नॉर्थ-ईस्ट से आते थे, इसलिए उन्होंने वहां बहुत काम किया। मैं मानता हूं, जरूर उस वक्त एक शुरुआत हुई थी, लेकिन वह शुरुआत sufficient नहीं थी। नॉर्थ-ईस्ट के जो aspirations हैं, उन aspirations को केवल और केवल प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया और उसके results आपके सामने हैं। आज अगर आप मणिपुर जायें, त्रिपुरा जायें, चाहे किसी भी नॉर्थ-ईस्ट के स्टेट में जायें, वहां जो काम की गति है, वह काम की गति दिखती है और आंकड़े आपके सामने हैं, results आपके सामने हैं। 2009 से 2014 के बीच में मात्र 2,122 करोड़ रुपये का investment नॉर्थ-ईस्ट में होता था, उसे almost ढाई गुना बढ़ा कर मोदी जी ने 2014 से 2019 के बीच में 5,531 करोड़ रुपये किया है और वे वहां पर भी रुके नहीं हैं। इस वर्ष 9,970 करोड़ रुपये का नॉर्थ-ईस्ट के लिए allocation है और वहां काम दिख रहा है। जो भी साथी नॉर्थ-ईस्ट जायें, आप वहां जाकर देखें, तो वास्तव में वहां पर काम दिख रहा है।

Freight corridor की बात आई। 'Vision Document' हमारे समय में किया गया था, यह concept note हमने दिया था - यह किया था, हमने यह काम किया। काम क्या किया? अच्छी बात है, आपने एक document दिया, अच्छी बात है, आपने एक concept दिया, लेकिन क्या देश केवल concept पर चलेगा? आपको काम तो दिखाना पड़ेगा। तो काम की बात अगर करें, तो 2004 में यह concept note आया, 2006 में foundation stone lay किया गया, लेकिन 2014 तक कितने किलोमीटर कमीशन हुए, ज़ीरो-सिर्फ ज़ीरो। यह कंडीशन थी। आज कितने किलोमीटर कमीशन हुए हैं, 1,010 किलोमीटर। मान्यवर LoP साहब, मैं आपका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता। हम किसी का क्रेडिट क्यों छीनें, आपके क्रेडिट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। टूजी है, कोल है, कॉमनवेल्थ है, बहुत सारी क्रेडिट की चीज़ें हैं, हमें आपका क्रेडिट नहीं चाहिए। हमें आपका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: I am not yielding, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*..

श्री अश्वनी वैष्णव : मैंने ऐसी कोई गलत चीज़ बोली भी नहीं है। मैंने ऐसा कोई unparliamentary word नहीं बोला है, जिसके कारण मुझे yield करना पड़े। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*.. He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अश्वनी वैष्णव : उपसभापति जी, आप कहें तो...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister has to yield. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता और आपको भी मेरी वजह से तकलीफ नहीं होगी। मेरी जो अवधि थी, मैंने जो काम किया, यहीं ex-Prime Minister बैठे हैं, उनसे पूछिये, कितने projects पड़े हुए थे, उनको हम कैसे लाये। टूजी स्पेक्ट्रम - ये सारी चीज़ें *

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलें, केवल आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...माननीय मंत्री जी, आप बोलें। ...**(व्यवधान)**... अन्य किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**... Please. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*... No, please. ...*(Interruptions)*... Please, no. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: #

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिये। माननीय LoP अपनी बात कह चुके हैं। आप सब सात घंटे बहस कर चुके हैं और माननीय LoP साहब, आप 46 मिनट बोल चुके हैं। प्लीज़, आप मंत्री जी को सुनिये।

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय उपसभापति जी, मान्यवर सांसद ने जब भी, जो भी अपना वक्तव्य रखा, ...**(व्यवधान)**... मैंने शान्ति से एक-एक मान्यवर सांसद का वक्तव्य सुना। इसके अलावा भी मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हमारा office open House है, आप कभी भी पधारें, किसी भी point

* Expunged as ordered by the Chair.

Not recorded.

पर आयें, किसी भी विषय पर आयें, मैं चर्चा के लिए हाजिर हूँ और जरूर करूंगा। आपने जो specific point बोला, इसीलिए मुझे specific जवाब देना पड़ा, वरना मैं इस बात को नहीं कहता। ...**(व्यवधान)**... बिल्कुल नहीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़। सीट पर बैठ कर न बोलें। ...**(व्यवधान)**... यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, आप आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, माननीय सदस्य बैठ कर आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय उपसभापति महोदय, रेलवे एक unique organization है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आपकी बात के अलावा कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय उपसभापति महोदय, रेलवे एक unique organization है। इसका एक बहुत important social obligation है। ...**(व्यवधान)**... इसका एक बहुत important social obligation है। साथ ही साथ, रेलवे से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह commercially भी viable हो। ये जो दो बड़े constraints हैं, इन दोनों constraints के बीच में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्लीज़। सीट पर बैठ कर बात न करें।

श्री अश्वनी वैष्णव : इन दोनों constraints के बीच में कैसे रेलवे को आगे ले जाना है, मैं अगले करीब दस मिनट तक उस विषय पर रहूँगा।

माननीय उपसभापति जी, आज भारतीय रेलवे साल में करीब-करीब 800 करोड़ passengers लेकर जाती है। हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, कई passengers एक से अधिक बार travel करते हैं, तो आज हम लोग 800 करोड़ passengers पर हैं। माल ढुलाई में कई वर्षों तक हम लोग करीब-करीब एक हजार मिलियन टन के आसपास थे। पिछले 4-5 वर्षों में इस पर बहुत मेहनत हुई, काम हुआ और हम 1,200 मिलियन टन पर आए और 1,200 मिलियन टन के बाद इस बार अंदाज़न 31 मार्च तक हम लोग करीब 1,400 मिलियन टन पर पहुँचेंगे। यह भी अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि विश्व में केवल तीन देश हैं - USA, Russia and China, जिनके बारे में मान्यवर एलओपी साहब ने भी चर्चा की थी, जो इतनी बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई करते हैं, cargo carry करते हैं। हम लोग 1,400 मिलियन टन को cross करने के बाद करीब-करीब Top Three में रहेंगे। करीब-करीब 2 लाख करोड़ का revenue है, करीब 2 लाख 40 हजार करोड़ का capital investment का बजट है और करीब एक करोड़ का रेल परिवार है। अगले 10 वर्षों में हमारे देश की जो aspirations हैं, हमारे नागरिकों की aspirations हैं, भारतीय जनता की जो aspirations हैं, हमारे आने वाली generations की जो aspirations हैं, अगर उनको हमें पूरा करना है, तो हमें आने वाले 10 वर्षों में target करना पड़ेगा कि हम लोग कम से

कम 800 करोड़ से 1,000 करोड़ passengers पर जाएँ और हमें 1,400 मिलियन टन से 3,000 मिलियन टन पर जाने का aspiration लेना पड़ेगा। अगर हम वह नहीं लेंगे, तो हम कभी भी जो passenger का fare है, उसको cross-subsidize नहीं कर पाएँगे। इसके लिए हमें cargo को कम से कम दोगुना, ढाई गुना बढ़ाना पड़ेगा। Freight charge नहीं, amount, volume. हमें करीब-करीब 3.5 लाख करोड़ revenue पर पहुँचना पड़ेगा और करीब 3 लाख करोड़ का investment हर साल करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इस देश की aspirations को meet कर पाएँगे। इन सबको करने के लिए आज क्या steps लिए जा रहे हैं, अगर ये steps हम आज लेंगे, तभी जाकर इनके results आने वाले 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में आने लगेंगे। यात्रियों की दृष्टि से, हमारी भारतीय जनता की दृष्टि से, आम नागरिकों की दृष्टि से सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हैं स्टेशंस। माननीय उपसभापति जी, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले किस तरह की गंदगी रहती थी। आज आप किसी भी स्टेशन पर जाएँ, मुझसे जो भी माननीय सांसद मिलते हैं, सभी कहते हैं कि हम मानते हैं कि आज सफाई है। सफाई के पीछे ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज़।

श्री अश्वनी वैष्णव : कई चीज़ें हैं। एक तो साफ-सफाई, स्टेशंस में कई तरह के परिवर्तन, करीब 2.5 लाख से ज्यादा bio-toilets लगाना, इस तरह के कई सारे प्रयास हुए। साथ ही साथ, हम बाहर के किसी मॉडल को तो लाकर यहाँ थोप नहीं सकते। हमें अपनी जमीन के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना खुद का एक मॉडल develop करना होता है। दो स्टेशंस बहुत सफल तरीके से world class बने - गाँधीनगर और रानी कमलापति। उनसे जो learning मिली है, उस learning से, उनसे जो सीखने को मिला, उससे हम आगामी वर्षों में, आगामी महीनों में 40-50-60 स्टेशंस किस तरह से लें और इस तरह से जो rapid construction की technology है, उसको हम जल्दी से जल्दी सीखें।

महोदय, हमारे यहाँ का हर स्टेशन अपने शहर का एक केन्द्र बने, वह केवल पैसेंजर्स के आने-जाने का स्थान बनकर न रह जाए, बल्कि उस शहर के जितने लोग हैं, उन सबके आने-जाने की जगह बने। इसके लिए वहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स हों, साथ ही इस तरह की व्यवस्था हो कि उस शहर की जो खास चीज़ें हैं, उन चीज़ों को उस स्टेशन पर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि आने-जाने वाले पैसेंजर्स उन चीज़ों का उपयोग कर सकें। इन सब धारणाओं को लेकर इस बार बजट में, 'One Station, One Product' की announcement की गई है और इस पर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर ज़ोनल रेलवे में केवल एक स्टेशन को लिया जा रहा है। देश भर से इसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं। हमारी जो unique diversity है, उस diversity को हम सब celebrate करते हैं, उसी तरह हमारा यह हाउस है, जो देश के different cultures को represent करता है। इस diversity को celebrate and propagate करने का एक विशेष तरीका है, जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स हैं, Visakhapatnam के Etikoppaka toys हैं, Howrah की Handloom Series हैं, असमी गमछा है, तिरुपति की कलमकारी साड़ी है, silver and stone jewellery of Jaleswar है, जो ओडिशा के northern part में मिलती है, राजकोट के टेराकोटा के बर्तन हैं, कोटा की डोरिया टेक्सटाइल्स है, बिलासपुर की

ढोकरा बेल मेटल से निर्मित कलाकृतियां हैं, जयपुर का सांगानेरी प्रिंट है। इस तरह उस शहर के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्टेशन पर लाया जाएगा, ताकि आने-जाने वाले यात्री उनको खरीद सकें। इससे उस स्टेशन के माध्यम से उनको अपने शहर की diversity को दिखाने का मौका मिल सकेगा।

पैसेंजर्स के बाद जो महत्वपूर्ण विषय आता है, वह ट्रेन्स का विषय है। 1950-60 में हमारे यहां ICF की टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद 1970-75 में LHB की टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उसके बाद कोई भी technological platform change नहीं किया गया, कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं आया। 2017 में प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया कि हमें हमारे देश में हमारे ही, हमारे इंजीनियर्स के द्वारा एक ऐसी World-class train develop करनी है, जो पूरी दुनिया की technologies को टक्कर दे सके, जिसका लोहा पूरी दुनिया माने।

माननीय उपसभापति जी, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इंजीनियर्स ने ही इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। यह संकल्प 2017 में लिया गया और 2019 में, सिर्फ दो वर्षों के अंदर-अंदर इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेन को उतार दिया गया। वैसे तो मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भूल चुका हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा-बहुत इंजीनियरिंग का ज्ञान है, जो समझ है, उसके अनुसार इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जनरली चार से सात वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने दिन-रात मेहनत की और 2019 में पहली दो 'वंदे भारत' ट्रेन्स को चालू करवा दिया गया। अभी तक ये दोनों रैक्स करीब-करीब 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं। इसमें बहुत सारी modifications आईं, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उस टेक्नोलॉजी को एपूव करने में टाइम लगता है। लेकिन इस ट्रेन को एपूव करने के बाद, इस बार लाल किले से माननीय प्रधान मंत्री जी 2023 तक 75 'वंदे भारत' ट्रेन्स manufacture करने का संकल्प लिया है। इन ट्रेन्स का version पिछली टेन्स से better होगा। उन ट्रेन्स का version-I था और इन ट्रेन्स का version-II होगा। महोदय, जिस तरह से design and manufacturing में अभी प्रोग्रेस चल रही है, ऐसे में जब नई ट्रेन्स के डिज़ाइन में हमें सफलता दिखी, उसके बाद इस बजट में 400 'वंदे भारत' ट्रेन्स चलाने की announcement हुई है।

महोदय, अभी कई माननीय सांसदों ने और हमारे माननीय एलओपी साहब ने भी यह कहा कि केवल दो ही ट्रेन्स चलाई गई हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये दो नई ट्रेन्स आप पिछले 40 वर्षों में भी तो बना सकते थे, लेकिन क्या आपने बनाई? उपसभापति जी, जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि उसको एपूव करना पड़ता है। आप जापान की बुलेट ट्रेन का उदाहरण ले सकते हैं। 1995 में उसकी E2 Series आई थी और 1997 में E3 Series आई थी। जब भी कोई भी नई Series बनती है, उसके बाद वह approve होती है, चलती है, फिर उसका experience देखा जाता है और फिर उसका new version आता है। Engineering का development तो ऐसे ही होता है।

2011 में जाकर E 5 आई, तो इस तरह से कोई अगर प्रश्न लगाये कि आपने केवल दो ट्रेन्स ही चलाई, तो उनको अपने पास्ट और अपने इतिहास में यह भी देखना चाहिए कि इससे पहले आपने क्या किया? क्या 1970 में ही हमें Electric Multiple Units (EMUs) में नहीं जाना चाहिए था? जब सारी दुनिया 1990 में ईएमयू की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी, तो हम शिफ्ट क्यों नहीं हुए,

हम लोकोमोटिव्स के हिसाब से ही ट्रेन्स को क्यों चलाते रहे? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आज मान्यवर एलओपी साहब पूछते हैं, लेकिन आपको अपने पिछले इतिहास को भी देखना चाहिए।

महोदय, बुलेट ट्रेन पर बहुत सारे प्रश्न आए, कई तरह की बातें हुई और कई तरह के प्रश्नचिह्न भी लगे कि बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? मैं इस सदन के सामने एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहूंगा कि हमारी next generation की aspirations क्या हैं, क्या हमारी aspirations में आधुनिक होना नहीं है, क्या हमारी aspirations में technological progress करना नहीं है, क्या हमारी aspirations में affordable journey, affordable good quality journey नहीं है? आप किसी भी नौजवान से पूछिये, आप किसी से भी पूछिये, हर कोई ट्रेन में ट्रेवल करना चाहता है। लेकिन ट्रेन्स एक ज़माने की गति से, एक ज़माने के तरीके से चलती आ रही थीं, इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या चाहते हुए भी आज ट्रेन्स में नहीं जाती है। लोग चाहते हैं कि वे ट्रेन्स में जाएं, लेकिन नहीं जा पाते हैं। अगर transport economics को देखें, तो हजार किलोमीटर से ज्यादा के लिए air is the most suitable. लेकिन भारत जैसे देश में, जहां 135 करोड़ जनसंख्या है, जहां 800 करोड़ trips आज भी हैं, जो कि हजार करोड़ की तरफ बढ़ने वाली हैं, उसमें हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजों को एडॉप्ट करना ही होगा। दुनिया भर में 25 देशों ने ऑलरेडी high-speed को, बुलेट को, Bullet is a colloquial name. उसका भी एक इतिहास है, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो जापान ने 160 केएमपीएच की ट्रेन बनाने की कोशिश की थी, उसके हिसाब से जो आज हमारी वंदे भारत ट्रेन है, तब उन्होंने इसका नाम बुलेट ट्रेन दिया था। इसका exact नाम Dangan Ressha है, देरेक भाई को पक्का पता होगा। 1939 में वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार के कारण बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट practically शेल्व हो गया, आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर 1964 में Shinkansen के नाम से यह ट्रेन आई। Shinkansen का अगर literal translation देखेंगे तो वह new trunk lines है, लेकिन जो बुलेट ट्रेन पहले का नाम चल रहा था, लोग colloquially उसी नाम से लोग जानने लगे। वही ट्रेन्स, जो ट्रेन्स आज जापान में आज E 5 सीरीज़ चल रही है, उसी ट्रेन्स को भारत में ला रहे हैं। साथ ही साथ entire civil work, entire track work सारा का सारा भारत के इंजीनियर्स कर रहे हैं, भारत की कम्पनियां कर रही हैं। यह टेक्नोलॉजी को absorb करने का एक तरीका है। हर सौ मीटर के बाद में geo-technical investigation entire soil, entire stretch का किया गया है। कहीं पर कोई compromise नहीं किया गया, कहीं कोई शॉर्ट कट नहीं लिया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए एशिया की सबसे बड़ी geo-technical laboratory सूरत में स्थापित हुई है और जो प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस के चलते आज करीब-करीब आठ किलोमीटर्स पर मंथ pillars cast हो रहे हैं, 29 किलोमीटर्स के पिलर्स कास्ट हो चुके हैं, close to 80 km. के एरिया में foundation कास्ट हो चुका है। इंजीनियर्स की टीम इसे बहुत अच्छे तरीके से सोच-समझकर कर रही है कि आगे जब मानसून आएगा तो मानसून में foundation का काम करना मुश्किल होता है। इसके लिए पहले पिलर्स ज्यादा कास्ट करो, जब मानसून की पीरियड आएगा तो ऊपर वाला girder और viaduct पूरा करेंगे। इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण देश की दिशा बदलती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को कोई vanity projects बोले, तो यह शर्म की बात है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब Delhi Metro आया था, तब भी इसी तरह की बातें हुई थीं। श्रद्धेय अटल जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला था, उनके समय में जब फोर लेन की बात आई थी, जब Golden

Quadrilateral की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की कहां जरूरत है, इस पर कोई 54 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च करेगा?

ऐसी बातें करना आसान होता है, क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन हिम्मत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर conceptualize करके उसको execute करना, वह एक बड़ी बात होती है, वह हमारी सरकार करती है। आपकी सरकार केवल vision रखती थी, हमारी सरकार execute करती है। वह काम करती है और हरेक point पर बारीकी से देख कर उसको आगे लेकर जाती है।

उपसभापति जी, मैं भारत की संस्कृति के बारे में एक विषय रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो, किस तरह से दुनिया में जो छोटी से छोटी चीज़ होती है, उसका अपने देश में लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्चर को दिखाते हैं, जबकि भारत की संस्कृति इतनी गौरवमयी है, इतनी गरिमामयी है, इतनी diverse है कि उसको दिखाने का एक बहुत अच्छा माध्यम रेलवे हो सकता है। इसीलिए 'भारत गौरव' के नाम से एक नयी श्रृंखला चालू की गयी है। इस नयी श्रृंखला के पहले 2 examples बहुत अच्छे हुए हैं। बीच में कोरोना आया, इसलिए रुक गये, लेकिन उसके बाद अब रामायण सर्किट हुई, काशी विश्वनाथ सर्किट हुई। इसके बाद और भी जो बहुत सारे सर्किट्स हैं, उन पर काम चलेगा। आप सब के सब इनसे जुड़ें, हरेक राज्य जुड़े। अभी कुछ दिनों पहले कर्णाटक सरकार के एक माननीय मंत्री जी आये थे। वे बहुत अच्छा concept लेकर आये थे। इस तरह से आप भी अपने-अपने राज्यों से, अपने-अपने क्षेत्रों से अपने concepts लेकर आयें। भारत एक है, भारत हमारा है। भारत किसका है, यह हमारा ही तो है। इसकी संस्कृति को अगर संजोना है, तो हमें ही संजोना है, इसे कोई बाहर से आकर तो देखने वाला नहीं है, बाहर से आकर तो इसे कोई संजोने वाला नहीं है। इसे हमें ही संजोना पड़ेगा, हमें ही इसको गौरवमयी करना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति जी, मैं छोटे किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए एक विषय रखूंगा। जो more than a truck load or full rake की बात है, उसके लिए रेलवे में बहुत अच्छे products हैं, बहुत अच्छी facilities हैं। ये कई वर्षों से develop होती आयी हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि ये 2014 के बाद में ही चालू हुई। छोटे किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए 'किसान रेल' का जो पहला experiment हुआ, उस experiment से learnings लेने के बाद अब एक बहुत ही अच्छा experiment चल रहा है कि किस तरह से एक नया product बनाया जाये। एक cuboid की भी संरचना की गयी तथा airlines में जो use होते हैं, उन containers का भी experiment चल रहा है। इसके अलावा एक और special container, छोटा container बना कर, जिससे हमारा जो MSME sector है, जो micro sector है और जो छोटे किसान हैं, वे देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में अपने सामान को एक सुलभ दर पर और एक safe way में पहुँचा सकें उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा experiment चल रहा है। बहुत जल्दी उसके अच्छे results आने चाहिए।

उपसभापति जी, आज लोक सभा में Guillotine भी है, तो इसी कारण मैं एकदम संक्षिप्त रहूँगा। डिबेट के दौरान कुछ और points raise किये गये थे। यदि मैं सारे points को कवर नहीं कर सकूँ, तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मुझे कभी भी मिलें, मैं जरूर आपको डिटेल में समझाऊँगा।

महोदय, सबसे पहला point operating ratio का है। Operating ratio में पहले की अपेक्षा परिवर्तन जरूर आया, जिसका सबसे बड़ा कारण Pay Commission की salaries रही। वह बढ़ी, तो उसके कारण operating ratio पर उसका impact हुआ, लेकिन वह बहुत जल्दी सुधर भी जायेगा। जैसे ही हमारा cargo का volume बढ़ेगा, वैसे-वैसे यह सुधर भी जायेगा।

दूसरा विषय privatization का आया। मेरे पूर्ववर्ती ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल जी ने बहुत clearly सदन में कहा, इस हाउस में भी कहा और उस हाउस में भी कहा कि रेलवे के privatization की कोई बात नहीं है। यह बहुत ही complex organization है, इसका social obligation है। वही बात मैं एकदम clearly दोहरा रहा हूँ कि इसमें रेलवे के privatization की कोई बात नहीं है।

तीसरा विषय stoppages का आया। Stoppages का rationalization इस भावना के साथ किया गया था कि trains को अगर टाइम पर चलाना है, तो यथा सम्भव उसको एक optimal way में चलाना चाहिए। दो साल पहले IIT, Bombay ने इसकी पूरी exercise की थी। IIT, Bombay के Operations Research Department ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसकी exercise की थी। किसी जगह पर अगर multiple trains की services मिल रही हैं या फिर पैसेंजर्स बहुत कम हैं, तो उसको rationalize किया गया। मुझे पता है, मेरे सामने कई माननीय सदस्यों ने यह विषय रखा है कि इसके कारण दिक्कत आयी है। हम उसको reconsider कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर उसका एक solution भी निकला है। उस हाउस में सुभाष चन्द्र बहेड़िया जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव भी दिया था। उस सुझाव पर भी already हमारे रेलवे के अधिकारियों ने काम करना चालू कर दिया है, तो उसका solution भी निकल जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि coaches की कंडिशन बहुत खराब है। पहले वाले ICF के coaches में जरूर दिक्कतें थीं, लेकिन अभी तीव्र गति से नये LHB coaches बन रहे हैं और इस साल 5,000 से अधिक ऐसे coaches बनाने का टारगेट है, तो on an average हर महीने 9-10 ट्रेन्स को replace कर दिया जाएगा। आप सबने देखा ही है कि already replace हो ही रहे हैं और इसमें बहुत तेजी से replacement होता रहेगा। माननीय उपसभापति महोदय, employment की बात आई। मैं employment के बारे में सबके सामने तथ्य रखना चाहूंगा। किसी ने कहा कि आपने तो पूरा employment ही बंद कर दिया, किसी ने कहा कि रेलवे में अब तो कोई employment ही नहीं होता, वहां तो ban हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, recruitment चल रहा है। वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में 2 लाख, 42 हजार, 709 appointments हुए थे, किन्तु उसके बाद वर्ष 2014 से अब तक already 3 लाख, 44 हजार, 646 appointments हो चुके हैं और अभी 1 लाख, 40 हजार, 713 positions पर recruitment चल रहा है। जरूर दिक्कत हुई थी, candidates और हमारे अधिकारियों के बीच एक misunderstanding हुई थी, लेकिन हमने अत्यंत संवेदना के साथ उस मैटर को deal करके जल्दी से उसे solve किया। हमने solve भी किया और संवाद भी किया तथा उस problem को आगे बढ़ने नहीं दिया। उपसभापति महोदय, discrimination की बात आई। किस राज्य को कितना allotment है, उसके आंकड़े रखे जा सकते हैं लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मैं एक-एक स्टेट का आंकड़ा नहीं रखूंगा किन्तु किसी भी स्टेट के साथ कोई discrimination नहीं है। मैं सभी से बहुत clearly request करूंगा कि आप

land allocation, land acquisition में हमारी मदद कीजिए। आप दो कदम चलेंगे, हम आपके साथ पांच कदम चलने को तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*.... No question.

श्री अश्वनी वैष्णव : उपसभापति महोदय, नये zones और नये divisions की बात आई। मैं सबके सामने scientifically और बहुत ही transparently यह कहना चाहूंगा कि हमें कहीं पर भी regional basis पर zone बनाने की बात नहीं करनी चाहिए। यदि हम रेलवे के हितैषी हैं और देश के हितैषी हैं, तो हमें रेलवे को operational basis पर ही चलते रहने देना चाहिए, उसमें कभी भी regionalism लाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में South Coast Railway का जो कमिटमेंट किया गया है, उस पर माननीय श्री प्रसन्न आचार्य जी ने पूछा था कि क्या वह regional basis पर होगा, वह regional basis पर नहीं होगा। उसमें जो कमिटमेंट किया गया है, उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा और उसमें तेजी से काम किया जायेगा। अभी पिछले छह महीने में South Coast Railway में बहुत प्रगति भी हुई है। माननीय उपसभापति महोदय, social responsibility पर प्रश्न किया गया था। रेलवे ने कई वर्षों तक अपने fares बहुत वाजिब रखे हैं। हमारे अधिकारियों ने calculation किया है कि आज रेलवे को passengers की यात्री सेवाओं में 1 रुपए, 16 पैसे प्रति किलोमीटर की cost आती है, लेकिन हम केवल 40 पैसे प्रति किलोमीटर charge करते हैं। इस प्रकार से करीब 62 हजार करोड़ रुपए की social obligation subsidy, passenger fare में दी जाती है। यह हमारी संवेदनशील सरकार है, हम उसके ऊपर निर्भर हैं, उस पर कायम हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। उपसभापति महोदय, separate Budget की बात आई। separate Budget जरूरी था। जैसा मैंने शुरू में कहा कि रेलवे की सबसे बड़ी समस्या इसमें investment की कमी थी। Capital investment के बिना रेलवे का development नहीं हो सकता था। पुरानी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में General Budget से जितना भी पैसा आता था, उसके against रेलवे को कुछ तो dividend देना पड़ता था और कुछ उसके ऊपर capital charge का interest भी लगता था। वह एक ऐसी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के कारण रेलवे में कभी भी enough capital आ ही नहीं पाया। रेलवे में sufficient capital आए, इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया था और यही दुनिया भर की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां यह कोई अनूठी व्यवस्था है। दुनिया भर में इसी तरह से है कि जो देश का बजट होता है, उसी बजट से capital investment का प्रावधान किया जाता है। इस Railway Budget को General Budget में merge करने के कारण ही आपने देखा कि आज हम ढाई लाख करोड़ रुपए के capital investment का allocation कर पाए, जो कि पुरानी व्यवस्था में संभव ही नहीं था।

यह बहुत जरूरी स्टेप था, इसमें कहीं किसी को doubt करने की जरूरत नहीं है कि उससे हमारी रेलवे की importance कम होगी। रेलवे की importance कम नहीं हुई, बल्कि इससे रेलवे की व्यवस्था में और ज्यादा facilities बढ़ीं तथा सुधार आया।

सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात आई, यह प्रोजेक्ट केरल का एक बहुत ही complex project है और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि किसी भी 63,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, 63,000 करोड़ रुपए का estimate स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन हमें

लगाता है कि यह एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा। उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के हिसाब से बनाया गया है और वह inter-operable नहीं है, यानी उन ट्रेक्स पर दूसरी ट्रेन्स नहीं चल सकती हैं। उसको standard gauge के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसलिए standard gauge पर broad gauge की गाड़ी नहीं चल सकती है। और भी कई सारी technical problems हैं, ecological issues भी हैं, environmental issues भी हैं, पब्लिक का भी एक बहुत serious agitation है। मेरा केरल के माननीय सांसदों से निवेदन है, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, सभी मान्यवर सांसदों से मेरा एक ही निवेदन है कि इसको संवेदना के साथ systemically बहुत ही सही तरीके से सोच समझ कर आगे ले जाना चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी न करें और जो भी फैसला होगा, वह fair decision होगा। मेरा आप सबसे ऐसा निवेदन है कि इस संबंध में कहीं पर भी मन में doubt न लाएँ, क्योंकि एक fair decision होगा, अच्छा फैसला होगा, जो केरल के हित में होगा।

उपसभापति महोदय, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय आए। मैं निवेदन करूँगा कि अगर किसी भी सांसद महोदय का कोई भी individual point हो, उस प्वाइंट को लेकर वे कभी भी आ सकते हैं, मैं तुरंत वहीं पर ऑफिस में ही अपने ऑफिसर्स को बुला लूँगा और उसको हम solve कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो solvable नहीं है। माननीय ठाकुर साहब ने कल बहुत ही पीड़ा के साथ कहा था, मैंने जाने के बाद तुरंत पूछा, तो पता चला कि हाँ, हमारे ऑफिसर्स से गलती जरूर हुई थी। मैंने उनको कहा था कि आप सात दिन के अंदर-अंदर वहाँ पर जाकर विज़िट कीजिएगा, लेकिन उन्होंने विज़िट नहीं किया। इसके लिए उनको अच्छी डाँट पड़ी है। आपकी बात का समाधान होगा, मुझे पूरी आशा है।

DR. M. THAMBIDURAI: Please respond to the issues of Tamil Nadu.

श्री अश्वनी वैष्णव : उपसभापति महोदय, मान्यवर सांसद महोदय तमिलनाडु के बारे में कह रहे हैं। आपने अच्छा किया कि आपने मुझे याद दिलाया।

Hon. Deputy Chairman, Sir, there are 27 projects with a length of about 3128 kilometres; project cost is estimated to be about Rs.30,961 crore. The allotment made to the State is about Rs.3,800 crore. It is not Rs.58 crore or somebody used the figure as Rs.380 crore. It is Rs.3,800 plus crore. That is a record allocation for Tamil Nadu. It has never been allotted that much amount. Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, my request to the Government of Tamil Nadu is that please help us acquire 1,544 hectares of land that is required. Only 200-odd hectares of land has been acquired so far. Much more help is needed from the Government of Tamil Nadu. Then only, the projects can succeed.

उपसभापति महोदय, मैं इसी सदन में कहना भी चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो कि बहुत proactive होकर land acquisition और law and order में मदद भी कर रही हैं, इसलिए वहाँ पर progress भी बहुत अच्छी है। रेलवे का तो ऐसा है कि अगर

प्रोग्रेस हुई, तो naturally अगली बार allocation बढ़ाने में सुविधा रहती है, मदद रहती है। इसी vision और इन्हीं points के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।...**(व्यवधान)**... बहुत सारे विषय रहेंगे।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. LoP Saheb, you are a very senior Member. Please! उपसभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ भारत के इंजीनियर्स की और 'आत्मनिर्भर भारत' की एक और उपलब्धि आपके सामने रखना चाहूँगा और वह है Automatic Train Protection System, 'कवच'। कई वर्षों से देश की रेलवे की एक जरूरत थी, जो कि आप एक vision document में रखते थे, लेकिन प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को inspire करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, जिसकी आज वर्ल्ड में चर्चा हो रही है।

जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। हमें अपने इंजीनियर्स से क्वेश्चंस करने के बचाए उन पर गर्व करना चाहिए, हमारे टैलेंट पर गर्व करना चाहिए। हमारी सरकार अपने इंजीनियर्स के टैलेंट पर विश्वास रखती है, इसीलिए मैं स्वयं ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे जरनल मैनेजर साहब बोल रहे थे कि साहब, आप मत चढ़िए, कोई बात नहीं, ट्रेन को चलने दीजिए, लेकिन सच में बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। मैं इस सदन में उन इंजीनियर्स की हौसला-बढ़ाई के लिए निवेदन करूँगा कि आप सभी उनका हौसला बढ़ाएं। माननीय उपसभापति महोदय, इस तरह से, इस multidimensional vision के साथ रेलवे आगे बढ़ रहा है।

माननीय सदस्य देरेक ओब्राईन साहब कह रहे थे कि पीएमओ का डिस्कशन है। हाँ, हमें गर्व है कि हमें प्रधान मंत्री जी आगे सोचने के लिए गाइड करते हैं, एडवाइज करते हैं। आपकी तरह नहीं, जो किसी extra constitutional authority से decision लेने जाना पड़ता था। प्रधान मंत्री जी constitutional authority हैं, यह उनका संवैधानिक हक है, अगर उसके हिसाब से हम उनकी guidance लेते हैं, तो इसमें आपको कटाक्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, when hon. LoP spoke, he made an expression * I request that it should be removed. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It would be examined. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Now, Special Mentions. ...*(Interruptions)*... The discussion on Railways is over. ...*(Interruptions)*... Now, Special Mentions. Shrimati Shanta Chhetri. ...*(Interruptions)*... श्रीमती शांता क्षत्री जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

* Expunged as ordered by the Chair.

SPECIAL MENTIONS - Contd.**Need to restore Darjeeling Himalayan Railways designated as a UNESCO World Heritage site**

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, Darjeeling Himalayan Railway is designated as a UNESCO World Heritage Site popularly known as "The Mountain Railways of India." The passenger train that was in operation from Darjeeling to Kurseong on a daily basis is non-operational since 2019. It had served till then as the lifeline for the hill community apart from being a huge tourist attraction.

I humbly request the hon. Railway Ministry to urgently look into the matter and restore the railway services between Kurseong and Darjeeling. Thank you, Sir.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Hardwar Dubey, not present. Shri V. Vijayasai Reddy.

Need to reduce Central taxes on petrol and make cesses on it shareable with States

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, high petrol prices have been burning a hole in the common man's pocket. The Centre may blame this on the rise in global crude oil prices but the reality remains that Central taxes on petrol have tripled in the eight years of the present Government. In 2014, consumers were paying Rs.9.48 as tax per litre of petrol whereas today, they are paying Rs.27.90. Overall, the Centre has increased its tax revenue from petroleum products by 223 per cent, from Rs.1.15 lakh crore in Financial Year 2014-15 to Rs.3.72 lakh crore in Financial Year 2020-21.

On many occasions, the Centre has also appealed to the States to reduce VAT on petrol. Out of every Rs.100 it earns as tax from petrol, it shares just Rs.2 with the